सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 01, अंक 360, नई दिल्ली । शनिवार, 09 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा।

03 ईडी के छापे का खेल, पूछते हैं, बीजेपी या जेल: केजरीवाल

06 जीवन को समझिए

08 देवभूमि के स्वरूप को बदलने नही दिया जाएगा:- सीएम धामी

दिल्ली मेट्रो का खास सॉफ्टवेयर लॉन्च, हर साल 5 लाख पेज की होगी बचत; ड्राइवरों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी होगा

DMRC ने स्वदेशी क्रू प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का इस्तेमाल शुरू किया है। इस तकनीक के माध्यम से विभाग हर वर्ष करीब पांच लाख कागज के पेज बचाएगा। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो में करीब 1200 चालक हैं। उनके प्रतिदिन के ड्यूटी रोस्टर तैयार करने ब्रेथ एनालाइजर जांच का रिकार्ड रखने अवकाश कर्मचारियों की शिकायतें इत्यादि कई अन्य विभागीय कार्यों के लिए अभी रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बृहस्पतिवार को स्वदेशी क्रू प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का इस्तेमाल शुरू किया है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रणाली के इस्तेमाल के लिए विशेष कियोस्क भी तैयार किए गए हैं।

मेट्रो नेटवर्क पर 14 जगहों पर ये कियोस्क लगाए गए हैं। इसके माध्यम से मेट्रो के चालकों की प्रतिदिन की रोस्टर तैयार होने के साथ-साथ ब्रेथ एनालाइजर जांच भी इस डिजिटल कियोस्क से हो सकेगी। ताकि शराब के नशे में कोई चालक ड्यटी पर मौजूद न रहने पाए।

डीएमआरसी का दवा है कि इस तकनीक के माध्यम से विभाग हर वर्ष करीब पांच लाख कागज के पेज बचाएगा। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो में करीब

1200 चालक हैं। उनके प्रतिदिन के ड्यूटी रोस्टर तैयार करने, ब्रेथ एनालाइजर जांच का रिकार्ड रखने, अवकाश, कर्मचारियों की शिकायतें इत्यादि कई अन्य विभागीय कार्यों के लिए अभी रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है।

अब ये तमाम काम क्रू प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से हो सकेंगे। इस प्रणाली के माध्यम से मेट्रो चालक, लाइन सुपरवाइजर मेट्रो ट्रेन, ट्रैक, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) में कोई खराबी और सिविल कार्य में कोई दिक्कत आने पर इसके माध्यम से आनलाइन रिपोर्ट कर सकेंगे। जिससे संबंधित अधिकारी देख सकेंगे। इससे समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। डीएमआरसी का कहना है कि पांच लाख कागज के पेज के लिए 417 पेड़ काटने पड़ते हैं।

वंदे भारत ट्रेन अब दुर्ग से विशाखापट्टनम तक दौड़ेगी

परिवहन विशेष न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ को एक और वंदेभारत ट्रेन मिलने जा रही है। इस समय नागपुर से बिलासपुर तक एक वंदेभारत पूरी सफलता के साथ चल रही है। आज प्राप्त सूचनानुसार दूसरी वंदेभारत एक्सप्रेस दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली है। इसे 12 मार्च को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट ने अपने टीटीई विंग को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्टाफ रिजर्व करने कहा गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वंदेभारत एक्सप्रेस स्लीपर कोच वाली होगी या परंपरागत सिटिंग और चेयरकार वाली होगी। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम के लिए यात्रियों की अधिकता और कम समय में सफर की सुविधा की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला किया है। इस समय कोरबा से विशाखापट्टनम के लिए ओवर नाइट लिंक एक्स्प्रेस के साथ पुरी, भगत की कोठी, समता एक्स्प्रेस जैसी ट्रेने उपलब्ध है। एक दो दिन में वंदेभारत एक्सप्रेस की विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी जाएगी।

गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, दो भाइयों की मौके पर मौत

यूपी के हापुड़ स्थित बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 09 पर शुक्रवार सुबह तड़के गलत दिशा में चल रही बोलेरो गाड़ी ने सामने से बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। भाइयों की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। हरियाणा के गुरुग्राम के सैक्टर-14 के निवासी विकास श्रीवास्तव (24) और उसका छोटा भाई विशाल श्रीवास्तव (22) पुत्र राधेश्याम श्रीवास्तव देर रात को अपने घर से अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए बुलेट बाइक से निकले थे। दोनों जैसे ही बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरोली गांव के पास पहुंचे तो सामने से गलत दिशा से आती हुई बोलेरो गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी।

द्वारका एक्सप्रेस: 18 KM तक का रोड शो करेंगे PM, होगी 40 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुग्राम में 11 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर एसपीजी के एआईजी ने अपनी टीम के साथ रैली स्थल का दौरा किया।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए वह 18 किमी की दूरी कार के काफिले से करेंगे। उसके बाद वह रैली स्थल पर पहुंचेंगे। रैली स्थल के पीछे बन रहे हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर से उनकी वापसी होगी। एसपीजी एआईजी के नेतृत्व में एक टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची। जिसने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पूरे स्थल का निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुग्राम में 11 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर एसपीजी के एआईजी ने अपनी टीम के साथ रैली स्थल का दौरा किया। जहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव व अन्य अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान बजघेड़ा बॉर्डर से रैली स्थल तक प्रधानमंत्री के काफिला कार से आने की बात तय हुई। रैली को संबोधित करने के बाद उनकी वापसी हेलीकॉप्टर से होगी। मंच से करीब 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही हेलीपैड बन रहा है। जहां से उनकी वापसी होगी।

कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप में भव्य तरीके के किया जा सके इसे लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव व पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने आयोजन स्थल पर ही जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिंदुवार की जाने वाली तैयारियों के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों का निर्वहन करने से संबंधित निर्देश दिए। एसपीजी की टीम रैली स्थल पर दूसरी बार पहुंची थी।

करीब डेढ़ घंटे तक प्रधानमंत्री गुरुग्राम की सीमा में रहेंगे।

बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्य दायित्वों की चर्चा कर चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, भोजन, वाहन, विद्युत, बैठने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को उचित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाने वाली प्रदर्शनी, हेल्प डेस्क एवं इसके उचित प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए। सीपी द्वारा उचित ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप में भव्य तरीके के किया जा सके इसे लेकर प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था संपन्न करें। प्रशासन की ओर से 40 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।

कर्नाटक सरकार ने वापस ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, माना "महिलाओं के लिए असुरक्षित"

परिवहन विशेष न्यूज

कर्नाटक सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के संचालन पर रोक लगा दी है। इन्हें ₹महिलाओं के लिए असुरक्षित₹ और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में पाए जाने के बाद यह रोक लगाई गई है।

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के संचालन पर रोक लगा दी है। इन्हें ₹महिलाओं के लिए असुरक्षित₹ और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में पाए जाने के बाद यह रोक लगाई गई है।

एक सरकारी आदेश में सूचित किया गया है कि 2021 की कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को वापस ले लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ₹यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ निजी एप-आधारित कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। और परिवहन के लिए गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को चला रही हैं।₹

आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और मैक्सी कैब के मालिकों और ड्राइवरों के साथ बाइक सवारों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और मामले भी दर्ज किए जाते थे। यह योजना परिवहन विभाग के लिए कर वसूली को भी कठिन बनाती थी।

अधिसूचना में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोपहिया बाइक टैक्सी पर यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया है।

ओला-उबर ड्राइवरों और मालिकों के संघ के अध्यक्ष, टैनवीर पाशा ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि 2021 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने बंगलूरू में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को अनुमति दे दी थी।

उन्होंने कहा, ₹हमारे विरोध के बावजूद, अनुमति वापस नहीं ली गई थी। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और सरकार को ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के जीवन पर इस अनुमति के प्रभाव के बारे में भी समझाने की कोशिश कर रहे थे।

पंचकूला को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, सात दिन करें मुफ्त यात्रा, जानें किराया और रूट

पंचकूला को शुक्रवार को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। खास बात यह है कि सात दिन लोग मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद किराया लगेगा।विधानसभा अध्यक्ष ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई। आने वाले समय पर लोगों की मांग के आधार पर बसों की संख्या में इजाफा भी किया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित बस स्टैंड से हरियाणा सिटी बस सर्विस के तहत पांच इलेक्ट्रिक एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शुरू होने से जहां नागरिकों को शहर के अंदर किफायती दरों पर बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी होगी, वहीं पर्यावरण को भी फायदा होगा। विस अध्यक्ष ने कहा कि यात्री सात दिनों तक इन बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और अन्य ने इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से शिव मंदिर सेक्टर-9 पंहुचे और भगवान शिव के दर्शन किए।

इससे पूर्व आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचकूला और करनाल में सिटी बस सर्विस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सिटी बस सर्विस देशभर में अपने आप में एक अनूठी पहल है। हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटिड के माध्यम से प्रदेश के बड़े शहरों फरीदाबाद, गुरूग्राम व मानेसर के साथ-साथ पानीपत और जगाधरी में यह बस सेवा पहले ही आरंभ हो चुकी है। अब जल्द ही इस सेवा का विस्तार करते हुए इसे रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत व रेवाड़ी में शुरू किया जाएगा। इन 12 शहरों के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा की सिटी बस सर्विस की शुरुआत होने से नागरिक सस्ती दरों पर एसी बसों में सफर कर सकेंगे।

विस अध्यक्ष ने सीएम का जताया आभार

हरियाणा विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने पर सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से नागरिकों को शहर के अंदर आवागमन में विशेष सुविधा तो होगी ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को 50 तक बढ़ाया जाएगा

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में पंचकूला में पांच इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है और आवश्यकता और लोगों की मांग के अनुसार इनकी संख्या को 50 तक बढ़ाया जाएगा। एक इलेक्ट्रिक बस में 45 लोगों के बैठने और 18 से 20 लोगों के खड़े होने की क्षमता है। 30 मिनट के चार्जिंग पर इसे 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। एक वर्ष में यह बस 70 हजार किलोमीटर का सफर तय करेगी। बस में यात्रियों की सुविधा के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, पैसेंजर इन्फोरमेंशन सिस्टम, पैनिक बटन, सीसीटीवी सर्विलांस और आईटीएमएस अनेबल्ड सिस्टम की सुविधा दी गई है।

30 रुपये होगा अधिकतम किराया

इन बसों में यात्री रियायती दरों पर सफर कर सकेंगे। 1 से 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 5 से 8 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 8 से 11 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, 11 से 14 किलोमीटर के लिए 25 रुपये और 14 से 17 किलोमीटर के लिए 30 रुपये किराया निर्धारित किया गया हैं। वर्तमान में निर्धारित रूटों के अनुसार बसें अधिकतम 16.03 किलोमीटर का सफर तय करेंगी।

इन रूटों पर चलेंगी बसें

इलेक्ट्रिक बस सेक्टर-5 बस स्टैंड से सेक्टर-4, 11, 10, 14-15, 12ए और अन्य रूटों से होती हुई पटियाला चौक जीरकपुर से सिंघपुरा पंहुचेगी। इसी प्रकार वापसी में सिंघपुर से इन्ही रूटों को कवर करते हुए सेक्टर-5 बस स्टैंड पहुंचेगी। फिर बस स्टैंड से सेक्टर-2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17-18 होकर हाउसिंग बोर्ड चौक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि पहली बस सेक्टर-5 बस स्टैंड से सुबह 6:30 बजे चलेगी और अंतिम बस सिंघपुरा से बस स्टैंड के लिए रात 8:45 बजे चलेगी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

हर क्षेत्र में मान-सम्मान हासिल करती हैं 'P' नाम की लड़कियां, जानिए इनकी 5 खूबियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नाम के पहले अक्षर से आप व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी बातें पता लगा सकते हैं। व्यक्ति का नाम उसकी तरक्की, करियर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। नाम सिर्फ व्यक्ति की पहचान ही नहीं बल्कि ग्रह-नक्षत्र और योग का प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम होते हैं। आज ऐसे ही आपको पी नाम से शुरु होने वाली लड़कियों के स्वभाव से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। आइए जानते हैं यह लड़कियां कैसे स्वभाव की मालकिन होती हैं।

जिद्दी होती हैं

इसन नाम की लड़कियां बहुत ही जिद्दी स्वभाव की होती हैं। यह हर क्षेत्र में मान-सम्मान हासिल करती हैं। सामने वाला इनके बारे में क्या सोचता है इस बात से इन्हें बहुत फर्क पड़ता है।

दिमाग की होती हैं तेज

यह लड़कियां मन से साफ होती हैं और इनके दिल में किसी के लिए भी कोई खोट नहीं होता। इन लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है।

अपनी रेप्यूटेशन का रखती हैं ध्यान

यह लड़कियां अपनी रेप्यूटेशन का खास ध्यान रखती हैं। पी नाम की लड़कियों के लिए इनकी छवि बहुत ही मायने रखती है।

प्यार के मामले में होती हैं अनलकी

यह लड़कियां प्यार के मामले में अनलकी होती हैं। इनका विचार यह प्यार तो करती हैं लेकिन इस मामले में किस्मत इनका साथ नहीं देती। कभी इनका प्रेमी से झगड़ा हो जाता है या फिर कभी प्रेमी उनकी छोड़ जाता है। इन लड़कियों की प्यार के मामले में किस्मत साथ नहीं देती।

नई-नई चीजें करती हैं एक्सपलोर

यह लड़कियां काफी बुद्धिमान होती है। इनमें नई-नई चीजों को एक्सपलोर करने की और नई चीजें सीखने की बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। अपने एक्साइटमेंट के चलते यह करियर में भी तरक्की जरुर हासिल करती हैं।

सभी गांठें नहीं होती हैं ब्रेस्ट कैंसर, करती हैं इन बीमारियां की ओर इशारा

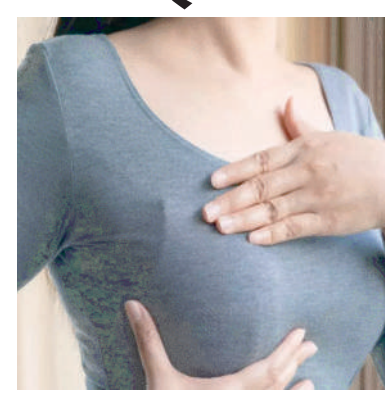

आजकल ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं। इसके चलते इसको लेकर जागरूकता महिलाओं के बीच बढ़ी है। महिलाओं अकसर खुद घर पर ही अपने ब्रेस्ट में गांठ के लिए चेक करती रहती हैं। ब्रेस्ट में किसी तरीका का परिवर्तन बहुत चिंता का कारण बन सकता है। ये तो समझ में आता है। लेकिन हर बार ब्रेस्ट में परिवर्तन की वजह ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती हैं।

ब्रेस्ट में कोई भी लक्षण, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ, निपल से स्राव या ब्रेस्ट में दर्द, आदि की जांच करके इसकी सही वजह एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। आपको बता दें ब्रेस्ट के जुड़ी और भी लक्षण होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ओर नहीं बल्कि किसी और बीमारी की ओर इशारा करते हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में....

फाइब्रोएडीनोमा

फाइब्रोएडीनोमा ब्रेस्ट का सबसे आम किस्म का ट्यूमर है। ज्यादातर ये 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में होते हैं। ब्रेस्ट examination के दौरान में ये अक्सर एक सख्त, गोल, चिकनी और रबड़ जैसी स्तन गांठ के रूप में दिखाई देते हैं। कई फ़ाइब्रोएडीनोमा का समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करके इलाज किया जा सकता है। ये भविष्य में स्तन कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाते हैं।

ब्रेस्ट सिस्ट

कभी-कभी, ब्रेस्ट में सिस्ट विकसित हो सकते हैं। सिस्ट तरल पदार्थ से भरे सेल्स होते हैं। ये breast tissue में गांठों या मैमोग्राम पर पाई जा सकती हैं। वे हमेशा लक्षण पैदा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे- जैसे सिस्ट बढ़ते हैं ब्रेस्ट में दर्द और sensitivity पैदा होती हैं। ये 35 से 60 साल की उम्र के बीच आम हैं, और पीरियड्स के साथ उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं ब्रेस्ट में सिस्ट ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है।

मास्टिटिस

ये ब्रेस्ट tissue में एक तरह की सूजन है जो ब्रेस्ट में दूध नलिकाओं के ब्लॉक होने से या बैक्टीरिया के कारण होती है। यह आमतौर पर ब्रेस्टफीड करवाने वाली महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन यह उन महिलाओं में भी हो सकता है जो ब्रेस्टफीड नहीं करवाती हैं। सूजन से ब्रेस्ट में दर्द, सूजन, गर्मी और लालिमा होती है। मास्टिटिस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और दर्दनिवारक दवाओं से किया जा सकता है।

पैपिलोमा

पेपिलोमा milk duct में एक वृद्धि है और यह निप्पल डिस्चार्ज के रूप में प्रकट हो सकता है। यह निप्पल के पीछे या बगल में एक छोटी गांठ के रूप में भी मौजूद हो सकता है। बायोप्सी यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या पेपिलोमा का इलाज करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि कभी-कभी उनमें असामान्य कोशिकाएं हो सकती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। वहीं इसका इलाज duct के बढ़े हुए आकार पर भी निर्भर करता है, यदि कई गांठें हैं या यदि वे लक्षण पैदा कर रहे हैं। पेपिलोमा को हटाने के लिए सर्जरी भी की जाती है।

असामान्य हाइपरप्लासिया (Atypical hyperplasia)

इसमें ब्रेस्ट की दूध नलिकाओं (milk ducts) में असामान्य कोशिकाओं यानी सेल्स बनते है। बता दें एटिपिकल हाइपरप्लासिया कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इससे जरूर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से, कभी-कभी उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। अक्सर, एक्सपर्ट्स कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। वहीं इसके इलाज के लिए खूब सारी screenings और दवाएं लेने की सलाह दी जाती है।

महिलाएं कृप्या ध्यान दें, हार्ट अटैक की वजह बन सकती है आपकी ये आदत, जोखिम से बचने के लिए करें 5 उपाय

एक नए अध्ययन में यह पता चला है कि अगर लंबे समय तक महिलाएं अनिद्रा की शिकार रहें और पर्याप्त नींद ना लें तो उनमें हृदय रोग की संभावना 70% बढ़ जाती है.

हम सभी जानते हैं कि नींद पूरी ना हो तो कई तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती है. एक नए शोध में यह खुलासा हुआ है कि अगर महिलाएं नींद पूरी नहीं ना लें और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहे तो वे बड़ी आसानी से दिल से जुड़ी बीमारियों से घिर सकती हैं. यही नहीं, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हुए इस शोध में यह भी पाया गया है कि अगर महिला रात के वक्त 7 घंटे की नींद नहीं लें तो वे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, मायोकार्डियो इंफ्रैक्शन जैसी समस्या की चपेट में भी आ सकती हैं. नींद की कमी इस खतरे को महिलाओं में 70 प्रतिशत अधिक बढ़ा देता है.

रिसर्च में क्या पाया गया

वैज्ञानिकों ने 2,517 महिलाओं पर यह रिसर्च किया. इस रिसर्च में पाया गया कि जो महिलाएं नींद की कमी या बार बार नींद टूटने की समस्यासे जूझ रही है (चार में से एक महिला), उनमें दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा 70 प्रतिशत पाया गया. वहीं जो महिला 5 घंटे से कमनींद ले रही है उनमें 72 प्रतिशत हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, आर्टरी डिजीज जैसी समस्या पाई गई.

यह भी लक्षण मिले

रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिन महिलाओं को लगातार नींद ना आने की समस्या रहती है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और यह यह बॉडी रिदम को भी प्रभावित कर रहा है, जो हार्ट अटैक के खतरे को 75 प्रतिशत बढ़ा रहा है.

अनिद्रा की परेशानी को ऐसे करें दूर

-हेल्थलाइन के मुताबिक, बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन, मंत्र और योग का सहारा लें.

-अगर आप सप्ताह में 150 मिनट व्यायाम करें तो इससे इनसोम्निया या अनिद्रा की परेशानी ठीक होने लगती है.

-तनाव की वजह से अगर नींद नहीं आ रही तो आप सेल्फ मसाज की मदद से इस परेशानी को दूर कर सकते हैं.

-डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड को शामिल करें और सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लें. चाय कॉफी से दूरी बनाएं.

-सोने से 2 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें, गुनगुने पानी से नहा के सोएं, रूम का लाइट ऑफ करें.

वजन कम करने से लेकर पाचन स्वस्थ रखेगी मिक्स दाल, जानिए इसके बेशुमार फायदे

दाल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है इसलिए घरों में एक बार इसे जरुर खाते हैं। दाल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। पहले समय में दालों को मिक्स करके बनाया जाता था इस तरह की दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों को बढ़ाती है। मिक्स दाल को कई दालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द की दाल इसमें शामिल की जाती है। इन सारी दालों में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। इस दाल का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मिक्स दाल खाने से शरीर को और क्या-क्या फायदे होंगे....

वजन होगा कम

मिक्स दाल का सेवन करने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरकर रखता है जिससे भूख कम लगती है। इससे खाने की इच्छा शक्ति भी कम होती है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मिक्स दाल में कैलोरी की मात्रा भी काफी कम मौजूद होती है। ऐसे में यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

बीमारियों से होगा बचाव

इसके अलावा मिक्स दाल खाने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी नियंत्रण में रहती हैं। इन दालों में फैट कम मात्रा में पाया जाता है जिससे दिल संबंधी बीमारियोंका जोखिम कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है।

हड्डियां बनेगी मजबूत

मिक्स दाल में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है यह हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को भी कम करने में भी मदद करती हैं। मिक्स दाल खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है।

पाचन रहेगा स्वस्थ

यह पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। इसका सेवन करने से पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या में भी आराम मिलता है। इसके अलावा मिक्स दाल खाने से अपच, गैस, बदहजमी और एसिडिटी से भी राहत मिलती है।

इम्यूनिटी बनेगी मजबूत

मिक्स दाल का सेवन करने से मौसमी बीमारियों से भी बचाव होता है क्योंकि इसमें विटामिन-सी काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। मिक्स दाल खाने से वायरल बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।

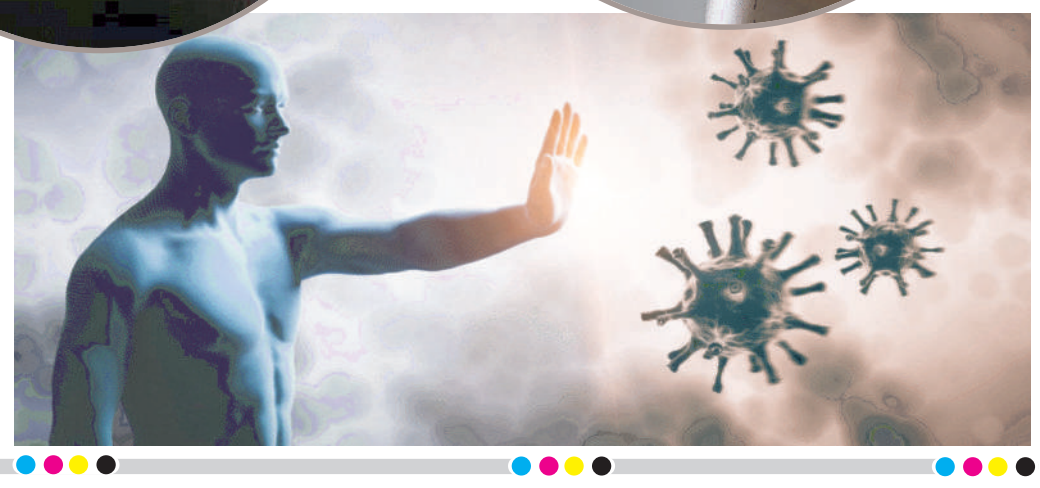

दिल्ली के गरीब कैदियों को जेल से रिहा होने में मिलेगी मदद, एलजी वीके सक्सेना ने लिया बड़ा फैसला

> इन कैदियों (161 विचाराधीन कैदी और 01 दोषी) को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि जेल विभाग द्वारा 23,79,000 रुपये आंकी गई है। इस योजना से न केवल गरीब कैदियों को लाभ होगा, बल्कि जेलों में भीड़भाड़ की समस्या का भी समाधान होगा। योजना का उद्देश्य उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो मुख्य रूप से सामाजिक रूप से कमजोर या कम शिक्षित हैं...

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की जेलों में कई ऐसे कैदी बंद हैं जो आर्थिक तंगी के कारण या उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने या जमानत राशि वहन करने में सक्षम न होने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसा फैसला किया है जिससे इन कैदियों को जेल से रिहा होने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने केंद्र सरकार की गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने वाली एक साल पुरानी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति और निगरानी समिति के गठन को मंजूरी दी। ये कैदी आर्थिक तंगी के कारण या तो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने या जमानत राशि वहन करने में सक्षम न होने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना है फंड

एलजी ने इस मामले पर संज्ञान लिया कि मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई, जबकि पूरा फंड केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाना है। जून में केंद्रीय गृह सचिव ने भी इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था।

162 कैदियों को लाभ होने की संभावना

सक्सेना ने पाया कि यह योजना केंद्रीय बजट 2023-24 का हिस्सा थी और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए एसओपी के अनुसार इसके शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार लागू की जाएगी। इस योजना से वर्तमान में दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद 162 कैदियों को लाभ होने की संभावना है, जो वित्तीय अक्षमता के कारण से रिहा नहीं हो पाए हैं।

इन कैदियों (161 विचाराधीन कैदी और 01 दोषी) को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि जेल विभाग द्वारा 23,79,000 रुपये आंकी गई है। इस योजना से न केवल गरीब कैदियों को लाभ होगा, बल्कि जेलों में भीड़भाड़ की समस्या का भी समाधान होगा। योजना का उद्देश्य उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो मुख्य रूप से सामाजिक रूप से कमजोर या कम शिक्षित हैं और निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं।

समिति में इन लोगों को शामिल करने का प्रस्ता

यह कदम उन्हें जेल से रिहा होने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में बंद कैदियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गरीब जेल कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। गृह विभाग, दिल्ली सरकार ने दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सशक्त समिति में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस उपायुक्त, संबंधित जेल के अधीक्षक /उपअधीक्षक संबंधित जेल के जज-इंचार्ज, जिला न्यायाधीश के नामिती के रूप में को शामिल करने का प्रस्ताव किया।

निगरानी समिति में प्रमुख सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव, डीआइजी/आइजी (जेल), उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, विशेष पुलिस आयुक्त शामिल होंगे।

बिना चीरा लगाए रेडियो सर्जरी की नई तकनीक से बुजुर्ग के ब्रेन ट्यूमर का सफलतापूर्वक इलाज

दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल ने ब्रेन के ट्यूमर का इलाज जाइरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी के जरिए करने में सफलता पाई है। इस तकनीक की मदद से 65 वर्षीय बुजुर्ग की सर्जरी की गई। इससे इलाज का खर्च भी ज्यादा नहीं आती है। अस्पताल में ऐसे मरीजों का किफायती शुल्क पर इलाज किया जाएगा। इस तकनीक से शरीर के अन्य हिस्सों की भी सर्जरी हो सकती है।

नई दिल्ली। अपोलो अस्पताल में जाइरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी मशीन से ब्रेन के ट्यूमर के इलाज की सुविधा शुरू की है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि दिल्ली का अपोलो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला अस्पताल है जहां यह अत्याधुनिक तकनीक की शुरुआत की गई है। इससे मरीज को बिना चीरा लगाए व बिना बेहोश किए 30 मिनट में हाई डोज रेडिएशन के जरिये ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की जा सकेगी। सर्जरी भी दर्द रहित होती है। सर्जरी बाद उसी दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

बृहस्पतिवार को अस्पताल में इस तकनीक की मदद से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित 65 वर्षीय बुजुर्ग की सर्जरी भी गई। डाक्टरों का कहना है कि एक ही बार में ट्यूमर के पूरे हिस्से को नष्ट कर दिया गया। वैसे रेडियो सर्जरी के लिए गामा नाइफ व साइबर नाइफ कई अस्पतालों में पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। अपोलो अस्पताल समूह के संस्थापक चेयरमैन डा. प्रताप चंद्र रेड्डी ने कहा कि नई मशीन पुरानी तकनीकों से ज्यादा अत्याधुनिक है। इलाज का खर्च भी उससे ज्यादा नहीं है। मरीजों को किफायती शुल्क पर इलाज किया जाएगा।

मस्तिष्क के स्वस्थ हिस्से को रेडिएशन से नुकसान नहीं

अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ. सुधीर त्यागी ने बताया कि नई तकनीक से 3.50 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर की रेडियो सर्जरी की जा सकती है। इससे मस्तिष्क के स्वस्थ हिस्से को रेडिएशन से नुकसान नहीं होता। शुरुआती स्टेज के ब्रेन कैंसर, बिनाइन ट्यूमर के इलाज में यह ज्यादा असरदार है। एडवांस स्टेज के मरीजों की ओपन सर्जरी के बाद रेडिएशन देकर इलाज में भी यह तकनीक मददगार होगी।

रेडियो सर्जरी के लिए फोटोन बीम का इस्तेमाल

अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ. गौरव त्यागी ने बताया कि गामा नाइफ में रेडिएशन के लिए गामा किरणें इस्तेमाल होती है। इसमें रेडिएशन सोर्स के रूप में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, जो बहुत पुरानी तकनीक है। इससे साइड इफेक्ट का जोखिम थोड़ा अधिक होता है। इस वजह से गामा नाइफ मशीन लगाने के लिए बड़े बंकर बनाने पड़ते हैं। साइबर नाइफ में रेडियो सर्जरी के लिए फोटोन बीम का इस्तेमाल होता है। इससे ब्रेन ट्यूमर के अलावा शरीर के कई अन्य हिस्सों के कैंसर ट्यूमर की सर्जरी हो सकती है।

रेडिएशन के लिए लीनियर एक्सीलेटर तकनीक का इस्तेमाल

अपोलो अस्पताल में शुरू नई मशीन से रेडिएशन का खतरा नहीं होता। इस लगाने के लिए बड़े बंकर की जरूरत नहीं होती। इसे सिर्फ ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता है, जो ज्यादा सटीक होता है। इसमें रेडिएशन के लिए लीनियर एक्सीलेटर तकनीक का इस्तेमाल होती है। मस्तिष्क के अन्य हिस्सों पर बिल्कुल दुष्प्रभाव नहीं होता।

कानपुर सिख नरसंहार 1984 के दोषियों को सजा दिलाने की ओर कोर्ट द्वारा एक और अहम फैसला

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। अखिल भारतीय दंगा पीड़ति राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष व सेक्रेटरी जनरल शिरोमणी अकाली दल, जत्थेदार कुलदीप सिंह भोगल ने प्रेस को दिये बयान में कहा कि कानपुर सिख नरसंहार, 1984 मामले में सुनवाई करते हुए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोषियों को सजा दिलवाने एवं पीड़तिों को इंसाफ दिलवाने की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए आदेश पारित किया कि कानपुर सिख नरसंहार में फाईल की गई चार्ज शीट में सरकार की तरफ से एक अनुभवी अधिवक्ता की नियुक्ति की जाए जिससे मुकदमे की सुनवाई एवं दोषियों की सजा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही पहले से खारजि चार मामलों में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में मुकदमें लड़ने के लिए भी सरकार समुचित व्यवस्था करे तथा अपीलों को दो हफ्तों के अंदर दाखिल करने की प्रक्रिया करे। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह भोगल एवं उनके अधिवक्ता श्री प्रसून कुमार एवं गुरबक्श सिंह को भी इस मामले में न्यायालय को वैकल्पिक नाम सुझाने एवं रिपोर्ट पर अपने प्रतिरोध को दर्ज कराने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। आज यू.पी. सरकार ने कोर्ट के आदेश के पालन में बवउचसपंदबम तमचवतज फाईल की, जिसमें 9 मामलों में जांच बंद करने, 11 मामलों में चार्जशीट फाईल करने

एवं चार मामलों में अपील फाईल करने की बात कही गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के आदेश से इस मामले में कार्यवाही का भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिल्ली के इन्चार्ज सुरिन्दर पाल सिंह समाना भी मौजूद थे।

चिराग फाउंडेशन द्वारा एनुअल फंक्शन एवं वृद्ध आश्रम का उद्घाटन

सकीना परवीन ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: चिराग फाउंडेशन के 9 साल पूरे होने पर एंव महिला दिवस के अवसर पर चिराग फाउंडेशन की संस्थापिका एवं अध्यक्ष सकीना परवीन के द्वारा एक का कार्यक्रम आयोजन किया गया। चिराग फाउंडेशन के 9 साल पूरे होने के अवसर पर वृद्ध आश्रम खोलने का निर्णय लिया था उसको पूरा करते हुए आज वृद्ध आश्रम का उद्घाटन भी किया गया ।

सकीना परवीन ने बताया कि फाउंडेशन तो बहुत चल रहे हैं हम चाहते हैं गरीबों मजलूमों की उम्मीद बनें और ऐसे बेसहारा की मदद करते रहें जो लोग बूढ़े हो गए हैं दुनिया में कोई नहीं उनके लिए ,हमने आज नई शुरुआत की है।

महिला दिवस के मौके पर आए सभी महिलाओं को संस्था का सर्टिफिकेट देखकर एवं गणमानीय लोगों को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी उपस्थित लोगो एंव फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियो का चिराग फाउंडेशन की अध्यक्ष सकीना परवीन ने शुक्रिया अदा किया ।

इस अवसर पर मौलाना अबरार मक्की, अब्दुल वाजिद खान आप नेता, फ़रीज़ अहमद, इमरान सैफी, डॉक्टर सफ़दर खान, मनोज श्रीवास्तव एस आई, शहजाद अली आदि ने अतिथि के रूप मे भाग लिया। जो बहने घरेलु हिंसा की पीड़ित है उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है तो चिराग फाउंडेशन को इस नंबर 9136965133 पर कॉल कर सकते हैं।

'पति से वित्तीय सहायता का अनुरोध करना क्रूरता नहीं', तलाक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

पत्नी द्वारा अपने पति से वित्तीय सहायता का अनुरोध करना क्रूरता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि पत्नी की घर खरीदने की इच्छा और इसके लिए पति से समर्थन मांगने के प्रयास को लालच या अन्यायपूर्ण मांग नहीं माना जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि पत्नी द्वारा अपने पति से वित्तीय सहायता के अनुरोध को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि अनुचित आरोप और शिकायतें ऐसे घातक घावों का कारण बनते हैं। इससे असहनीय मानसिक और शारीरिक कटुता पैदा होती है और पति-पत्नी के लिए एक साथ रहना असंभव हो जाता है। उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आइए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देते हुए की। तीन साल तक प्रेम-संबंध के बाद दोनों ने वर्ष 2010 में शादी कर ली थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति के माता-पिता उसके पंजाबी होने के कारण दहेज की अपेक्षा करते थे।

आजकल हिंदू संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और आपसी रिश्तों में भी वो बात नहीं रही और इसका कारण है संस्कारों का अभाव।

दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैंसला स्वागत योग्य है, खत्म होते संस्कारों का आभास है इसमें

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया जिसमें पति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था क्योंकि पत्नी को घर के काम नहीं करने थे और पति को उसके परिवार से अलग भी करना था, इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो बातें कही वो आजकल के युवा और उनके माता पिता के लिए एक बड़ी सीख है। आजकल हिंदू संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और आपसी रिश्तों में भी वो बात नहीं रही और इसका कारण है संस्कारों का अभाव।

हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहां की पति द्वारा पत्नी को घर के कामों के लिए कहना क्रूरता नहीं लेकिन पत्नी द्वारा पति को अलग रहने के लिए कहना क्रूरता के समान है। ये दोनों ही बातें आजकल समाज में देखी जा रहे हैं की पत्नी घर के काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होती और साथ ही परिवार में एकसाथ रहना भी उन्हें बंधन लगता है। आजकल स्थिति ये हैं की समानता और फ्रीडम के नाम पर बेसिक क्वालिटीज को ही किनारे कर दिया जा रहा है जिससे समाज से संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं और परिवार बिखरते जा रहे हैं।

एक घरेलू मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद एक पति द्वारा अपनी पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति को अपने परिवार से अलग रहने के लिए कहना क्रूरता के समान है। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने पति को तलाक की मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने एक पति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, "अगर एक विवाहित महिला को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है तो इसे नौकरानी के काम के बराबर नहीं माना जा सकता है और इसे अपने परिवार के लिए उसके प्यार और स्नेह के रूप में गिना जाएगा।"

पीठ ने यह भी कहा कि कुछ स्तरों में पति वित्तीय दायित्वों को वहन करता है और पत्नी घर की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। मौजूदा मामला भी ऐसा ही है। भले ही अपीलकर्ता पति ने प्रतिवादी पत्नी से घर का काम करने की अपेक्षा की हो, फिर भी इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रत्येक साथी अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार योगदान देता है।

दरअसल, दोनों की शादी 30 मार्च 2007 को हुई थी। इसके बाद 2 फरवरी 2008 को उनके बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद पति-पत्नी में विवाद हो गए। पत्नी ने पति के परिवार पर दहेज माँगने और क्रूरता के आरोप लगाए थे। पति का यह भी आरोप था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार को छोड़कर अलग रहने के लिए उस पर दबाव डालती है।

सीआईएसएफ में काम करने वाले पति ने कोर्ट को बताया कि वह पत्नी द्वरा घर के कामों में हाथ नहीं बँटाने, वैवाहिक घर छोड़ने के लिए कहने और उसे आपराधिक मामलों में झूठे फँसाने से वह व्यथित था। इस आधार पर वह अपनी से अलग होना चाहता था, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने इससे इनकार दिया। इसके बाद पति ने इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी पत्नी की इच्छाओं के आगे झुकते हुए पति ने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए एक अलग आवास की व्यवस्था की थी, लेकिन पत्नी ज्यादातर अपने माता-पिता के साथ रहती थी। अपने माता-पिता के साथ रहने का विकल्प चुनकर महिला ने न केवल अपने वैवाहिक दायित्वों की अनदेखी की, बल्कि पति को उसके बेटे से दूर रखकर उसके पितृत्व से भी वंचित कर दिया।

अदालत ने कहा कि अस्थायी अलगाव जीवनसाथी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है और महिला का संयुक्त परिवार में रहने का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने कहा कि एक बेटे का अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना नैतिक और कानूनी दायित्व है, खासकर ऐसे हालात में जब माता-पिता के पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है या फिर है तो नगण्य है।

"नरेंद्र बनाम के. मीना के मामले का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है कि एक बेटे को अपने परिवार से अलग होने के लिए कहना क्रूरता है। इसमें कहा गया था कि भारत में एक हिंदू बेटे के लिए आम बात नहीं है और ना ही शादी के बाद अपने परिवार से अलग होने की वांछनीय संस्कृति है।

अदालत ने कहा, "जब दोनों पक्ष विवाह के बंधन में बँधते हैं तो उनका इरादा भविष्य के जीवन की ज़िम्मेदारियों को साझा करना होता है। कई निर्णयों में यह पहले ही माना जा चुका है कि यदि एक विवाहित महिला को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है तो उसे नौकरानी के बराबर नहीं माना जाता, बल्कि उसे अपने परिवार के प्रति उसके प्यार और स्नेह के रूप में गिना जाता है।

दिल्ली में एक शादी ऐसी भी... तिहाड़ जेल से आएगा दूल्हा, ऑटोमेटिक हथियार के साथ सूट-बूट में होंगे पुलिसवाले

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के द्वारका में एक शादी ऐसी भी होने जा रही है जिसमें दूल्हा तिहाड़ जेल से आएगा। शादी जिस बैंक्वेट हाल होगी वह पहले ही किले में तब्दील हो चुका है। शादी के कार्यक्रम के दौरान सादे कपड़े में हाईटेक हथियार रखने वाले कमांडो तैनात रहेंगे। शादी के दौरान वेटरों और अन्य कर्मचारियों को पहचान के लिए आईडी दी जाएगी।

नई दिल्ली। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ 12 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के द्वारका सेक्टर-3 में संतोष गार्डन नामक बैंक्वेट हाल में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बैंक्वेट को गैंगस्टर संदीप के वकील ने 51 हजार रुपये में बुक किया है।

250 कमांडों हथियार के साथ रहेंगे तैनात

खास बात है कि शादी में हाईटेक हथियार रखने वाले SWAT (स्पेशल वेपन्स एंड टेक्निक्स) कमांडो के साथ 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इस दौरान स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और हरियाणा की सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) की टीमें मौजूद रहेंगी। संदीप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किसी भी घटना को रोकने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है।

जेल से विवाह स्थल तक पुलिस का पहरा

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम इस बार कोई मौका नहीं लेना चाहते। इसलिए, तिहाड़ से लेकर द्वारका में विवाह स्थल तक पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। संतोष गार्डन तिहाड़ जेल से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, संदीप को अपनी शादी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की इजाजत मिली है। अगले दिन 13 मार्च को जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए उन्हें हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव में उनके गृहनगर ले जाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि शादी के कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कुछ पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में हथियारों के साथ कार्यक्रम स्थल पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पुलिस ने कहा कि संदीप को बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ ले जाया जाएगा।

चार बच्चों और लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही महिला ने किया सुसाइड, पुलिस ने बताई ये वजह

नोएडा के कोतवाली सेक्टर-58 क्षेत्र के नवादा गांव में अपने लिव-इन पार्टनर और चार बच्चों के साथ रह रही एक 32 वर्षीय महिला ने गुरुवार को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला का और उसके लिव-इन पार्टनर का रात को आपस में झगड़ा हुआ था।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-58 क्षेत्र के नवादा गांव में अपने लिव-इन पार्टनर और चार बच्चों के साथ रह रही एक 32 वर्षीय महिला ने बृहस्पतिवार को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला का और उसके लिव-इन पार्टनर का रात को आपस में झगड़ा हुआ था।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुष्पा नवादा गांव में चार बच्चों और लिव-इन पार्टनर अर्जुन के साथ रह रही थी। उसके लिव इन पार्टनर के भी दो बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को पुष्पा ने अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

महिला का पार्टनर के साथ हुआ था झगड़ा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि महिला और उसके पार्टनर के बीच बुधवार देर रात आपस में झगड़ा हुआ था। पुलिस को संदेह है कि दोनों के बीच हुए विवाद जिसके चलते महिला ने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि महिला के लिव-इन पार्टनर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगर मृतका के घर वाले इस मामले में कोई शिकायत करते हैं तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करेगी।

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति मुर्मु ने वायुसेना की चार युनिटों को किया सम्मानित, पढ़ें क्यों दिए जाते हैं ये पुरस्कार

परिवहन विशेष न्यूज

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पहुंचीं। एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें परेड कर सलामी दी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति का आगमन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। राष्ट्रपति एयरफोर्स के चार यूनिटों को सैन्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें राष्ट्रपति मानक दिया गया। यह सम्मान 25 वर्षों में सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है।

साहिबाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। यहां एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें परेड कर सलामी दी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति का आगमन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है।

राष्ट्रपति ने एयरफोर्स की चार यूनिटों को किया सम्मानित

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एयरफोर्स की चार यूनिटों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति एयरफोर्स के चार यूनिटों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया है।

इन्हें राष्ट्रपति मानक और रंग से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 25 वर्षों में सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। जिन चार यूनिटों को सम्मान दिया जाता है।

उसमें 45 स्क्वार्डन, 221 स्क्वार्डन, 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट शामिल हैं। चारों यूनिट की ओर से ग्रुप कैप्टन एम सुरेंद्रन, ग्रुप कैप्टन शुभांकन, एयर आफिसर कमांडिंग आशुतोष वैद्य और कमांडिंग आफिसर ग्रुप कैप्टन विवेक शर्मा उपस्थित रहे।

एयरचीफ मार्शल, जनरल वीके सिंह और जतिन प्रसाद पहुंचे

आज के कार्यक्रम के लिए एयरचीफ मार्शल बीआर चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह और जतिन प्रसाद हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं।

पहली बार आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पहली बार गाजियाबाद आई हैं। ऐसे में शहर के लोगों में भी उनके आने का उत्साह है। खासकर बच्चे उनके आने को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि शहर के लोग उनकी झलक नहीं देख पाएंगे।

500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात

साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार को सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पहुंची हैं। अन्य कई वीवीआइपी और वीआइपी सेना के अधिकारी शामिल हैं, जिसके चलते इनकी सुरक्षा में पांच सौ से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। छतों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो निगरानी करेंगे। दिल्ली से आने वाले रूट पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

वाहन चालकों को परेशानी न हो यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल समेत 10 से अधिक अधिकारी भ्रमणशील हैं। पल-पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

17 साल से बिना बिजली के पढ़ाई के लिए छात्र मजबूर, 53 छात्रों ने छोड़ दिया स्कूल

ग्रेटर नोएडा के दादरी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल दादरी दो में 17 साल से बिजली की व्यवस्था नहीं है। छात्र सर्दी गर्मी और वर्षा में बिना बिजली के पढ़ने का मजबूर हैं। इसके साथ ही स्कूल का रास्ता खराब होने के कारण छात्र बंबे के ऊपर बिजली के खंभे से रास्ता पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस कारण 53 छात्रों ने स्कूल को छोड़ दिया है।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। 300 करोड़ रुपये की लागत से स्कूलों का कायाकल्प करने का दावा करने वाला बेसिक शिक्षा विभाग दादरी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल दादरी दो में 17 साल से बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाया है। छात्र सर्दी, गर्मी और वर्षा में बिना बिजली के पढ़ने का मजबूर हैं। इसके साथ ही स्कूल का रास्ता खराब होने के कारण छात्र बंबे के ऊपर बिजली के खंभे से रास्ता पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण 53 छात्रों ने स्कूल को छोड़ दिया है।

पहले स्कूल में 117 छात्र नामांकित थे, लेकिन अब स्कूल में 64 छात्र ही बचे हैं। माननीयों के घर में एक मिनट के लिए भी बिजली गायब हो जाती है तो वह पूरा विभाग को सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन छात्र 17 साल से बिना बिजली पढ़ाई कर रहे हैं। इससे माननीयों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। देश के भविष्य को बिजली नहीं मिल पा रही। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के बिना छात्रों के उज्ज्वल 'भविष्य' की कल्पना करना बेमानी से कम नहीं होगा।

कक्षा एक में मात्र छह छात्र

बंबे से होकर गुजर कर स्कूल पहुंचने के कारण स्कूल में कक्षा एक में मात्र छह छात्र ही नामांकित हैं। छोटे बच्चे बंबे को पार करते हुए गिर न जाए, इसलिए अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। वहीं कई अभिभावकों ने बच्चों का नाम कटवा लिया है। बंबे की सफाई के दौरान सिल्ट को बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे होकर ही छात्र निकलते है।

खेत में बना स्कूल

शिक्षिकाओं ने बताया कि स्कूल खेतों के बीच में है, चारदीवारी न होने से असामाजिक तत्व आसपास घूमते रहते हैं। चुनाव ड्यूटी हो या और शिक्षकों के छुट्टी पर होने के दौरान खुद असुरक्षित महसूस होता है। छात्रों की सुरक्षा का डर हमेशा बना रहता है। कई बार सभी समस्याओं से विभाग को अवगत कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

रास्ते के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया है। जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। - दीपिका शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दादरी

स्कूल में छात्र संख्या

कक्षा	छात्र
एक	06
दो	18
तीन	16
चार	14
पांच	10

एल्विश यादव ने यूट्यूबर की कर दी पिटाई, मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगने का वीडियो किया था पोस्ट

कुछ दिन पहले मुंबई में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में एक्टर और पूर्व क्रिकेटर के बीच में मैच हुआ था। इसमें मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव गले लगे थे। इसी वीडियो को यूट्यूबर सागर ठाकुर ने पोस्ट किया था। इसके बाद एल्विश यादव ने उसकी पिटाई कर दी। इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

गुरुग्राम। ओटीटी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के एक यूट्यूबर सागर ठाकुर को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि एल्विश यादव पहले अपने साथियों के साथ आते हैं और फिर उसको थप्पड़ मारते हुए मारपीट करने लगते हैं। मामला गुरुवार रात का बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।

एल्विश के मुनव्वर से गले लगते वीडियो किया पोस्ट

कुछ दिन पहले मुंबई में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में एक्टर और पूर्व क्रिकेटर के बीच में मैच हुआ था। वहां पर एल्विश यादव भी खेल रहे थे। वहां पर एल्विश यादव ने कॉमेडियन और बिग बास-17 विनर मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगते दिख रहे थे। इस वीडियो को यूट्यूबर मैक्स्ट्रेन उर्फ सागर ठाकुर ने वीडियो पोस्ट कर दी। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और बृहस्पतिवार को दोनों ने मिलने का तय किया। इसके बाद मौके पर आए एल्विश यादव ने सागर ठाकुर के साथ मारपीट की।

मोदी पर निजी हमला कर विपक्ष ने चुनावों से पहले खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है

2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर एक और हमला किया था। अय्यर ने कहा था कि वो चायवाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान पर भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही थी। पीएम ने अय्यर की टिप्पणी पर जवाब अपने ही अंदाज में दिया था।

डॉ. आशीष वशिष्ट

20 सितंबर 2018 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में आदिवासी जिले डूंगरपुर के सागवाड़ा में एक जनसभा में एक कहावत का उपयोग करते हुए राफेल मामले में प्रधानमत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने पीएम पद की गरिमा का खयाल भी नहीं रखा। राहुल गांधी ने कहा, 'गली-गली में शोर है, देश का चैकीदार चोर है।' राहुल गांधी की चैकीदार चोर की टिप्पणी के बाद पूरे देश में इस शब्द को लेकर ही आंदोलन शुरू हो गया था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के आगे 'मैं भी चैकीदार' जैसे शब्द लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में, चौकीदार चोर है का नारा देने के कारण राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी।

3 मार्च 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में इंडी अलांयस की रैली में बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी के परिवारवाद वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो पत्नी के साथ नहीं रहते। कैसे जानेंगे कि परिवार क्या होता है?

लालू प्रसाद की आपत्तिजनक टिप्पणी के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के अदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके परिवार को लेकर किए गए हमले का परोक्ष रूप से जवाब दिया। पीएम ने कहा, 'मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। जिनका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है।'

पीएम मोदी की ओर से पूरे देश को अपना परिवार बताए जाने के कुछ देर बाद ही भाजपा ने नए अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान का नाम दिया गया 'मोदी का परिवार।' फिर क्या था बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बॉयो बदल दिया। वास्तव में, लालू के हमले को ही मोदी ने हथियार बनाते हुए अपने चुनावी अभियान में शामिल कर लिया। साल 2019 में भी पीएम मोदी ने विपक्ष के हमले से ही एक ऐसा हथियार निकाला और इस तरह अभियान चलाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सारी कोशिशें ध्वस्त हो गई थीं और भारतीय जनता पार्टी 2014 की तुलना में बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की थी।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने एक्स पर अपने बॉयो में 'मैं भी चौकीदार' लिखकर इस अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में बीजेपी के छोटे-बड़े नेताओं ने अपनी बॉयो में 'मैं भी चैकीदार' लिखना शुरू कर दिया। गली-गली पोस्टर लग गए। सिर पर टोपी आई जिस पर लिखा था- मैं भी चौकीदार। हर बड़ी हस्ती खुद को चौकीदार बताने लगी थी। चायवाला बनकर अगर पीएम रिक्शा, रेहड़ी-पटरी वाले तबके से जुड़ते हैं तो 'मैं भी चौकीदार' से उन्होंने एक बड़े तबके को खुद से जोड़ने की कोशिश की, वो प्रयोग सफल रहा। यह अभियान चुनाव खत्म होने तक जारी रहा। 2019 में जहां मैं भी चौकीदार नारा चर्चा में आया था तो वहीं अबकी बार मोदी का परिवार सुर्खियों में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बार विपक्ष ने फिर से वही गलती कर दी है।

2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने

पीएम मोदी पर एक और हमला किया था। अय्यर ने कहा था कि वो चायवाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इस बयान पर भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही थी। पीएम ने अय्यर की टिप्पणी पर जवाब अपने ही अंदाज में दिया था। मोदी ने चुनावी कैंपेन के दौरान खुद को चायवाला बताकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए थे। इस बयान को मुद्दा बनाया गया था और चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखे गए थे। उस वक्त भी इसी तरह बीजेपी ने उनके इस बयान को लपका था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस वक्त ना सिर्फ तालकटोरा स्टेडियम के बाहर चाय बेची थी बल्कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति ही 'चाय' पर केंद्रित हो गई थी।

2007 में गुजरात चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को 'मौत का सौदागर' बताया था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2017 में पीएम मोदी को नीच इंसान बताया था, गुजरात चुनाव के दौरान दिया गया ये नारा भाजपा ने जातिवाद से जोड़ दिया था। पीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस के लोग मुझे नीच कहते हैं। गुजरात के बेटे के इन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस को भारी पड़ेगा। प्रदेश के नतीजे इसके गवाह होंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की थी।

2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने अकेले तीन सौ के आंकड़ों को पार किया और 303 सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल रही। अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ ने इस जीत को और प्रचंड बना दिया। एनडीए ने लोकसभा की कुल 353 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए 92 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस के अकेले प्रदर्शन की बात करें तो काफी खींच-तान के बाद पार्टी को महज 52 सीटों पर सफलता मिली। भाजपा की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने एक बार फिर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। 2014 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस महज 44 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और उस बार भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिल पाया था।

2019 के आम चुनाव में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी पीएम मोदी के मुकाबले मैदान में थे। इस बार इंडी अलांयस मैदान में तो है, लेकिन उसकी ओर से कोई सर्वसम्मत चेहरा मैदान में नहीं है। विपक्ष को समझना चाहिए कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में चमत्कारी चेहरा है। उनकी नीतियों और फैसलों में खामी ढूंढ़कर जनता के सामने रखा जा सकता है लेकिन जब पीएम खुद को सबसे बड़ा ओबीसी नेता बता रहे हों, चुनाव करीब हो तब विपक्ष की एक गलती सारे समीकरण गड़बड़ा सकती है। अब परिवार वाले तंज पर ही देखिए कैसे पीएम ने रैली में भावुक अंदाज में देशभर के लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया। हां, पीएम ने कहा, 'मेरा भारत-मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा।' पश्चिम बंगाल के बारासात में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन-बेटी कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सालों तक परिवार से विरक्त रहा हूं। लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है।'

देश के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे तो पीएम मोदी पर लगातार कांग्रेस और विपक्ष अभद्र टिप्पणी और निजी हमले करते रहे हैं। कभी पीएम मोदी को रावण कहा गया तो कभी जहरीला सांप, कभी मौत का सौदागर कहा गया तो कभी चौकीदार चोर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष लगातार हमले करते रहा और पीएम मोदी सहजता से उन हमलों और टिप्पणियों को अपना हथियार बनाते रहे। इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने बैठे बैठाए भाजपा को मुद्दा थमा दिया है। भाजपा को 'मोदी का परिवार' अभ्यिान विपक्ष को भारी पड़ने वाला है।

(लेखक स्वतंत्र वरिष्ठ पत्रकार हैं)

BYD सील vs हुंडई आइकॉनिक 5 : किस प्रीमियम EV को खरीदने फायदे का सौदा? जानिए प्राइस से लेकर फीचर्स तक की डिटेल

BYD Seal को भारत में तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले बेस डायनामिक वेरिएंट है जिसमें 61.44 kWh बैटरी पैक और रियर-व्हील ड्राइव सेटअप है। इसका प्रीमियम वेरिएंट 82.56 kWh बैटरी से लैस है और ये रियर-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन को बरकरार रखता है। 308 बीएचपी और 360 एनएम टॉर्क के साथ ये ईवी 650 किलोमीटर की रेंज देती है। आइए दोनों के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। चीन की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक सेडान BYD Seal को 41 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। विशेष रूप से 'ब्लेड बैटरी' तकनीक के साथ पेश की जाने वाली EV इंडियन मार्केट में Hyundai Ioniq 5 को टक्कर देगी। आइए, इन दोनों प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जान लेते हैं।

बैटरी और मोटर

BYD Seal को भारत में तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले बेस डायनामिक वेरिएंट है, जिसमें 61.44 kWh बैटरी पैक और रियर-व्हील ड्राइव सेटअप है। हुड के नीचे 201 बीएचपी और 310 एनएम टॉर्क के साथ, यह वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 510 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज का वादा करता है।

इसका प्रीमियम वेरिएंट 82.56 kWh बैटरी से लैस है और ये रियर-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन को बरकरार रखता है। 308 बीएचपी और 360 एनएम टॉर्क के साथ ये ईवी 650 किलोमीटर की रेंज देती है।

वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन BYD Seal परफॉर्मेंस वेरिएंट अपनी 82.56 kWh बैटरी और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम प्रदान करता है और ये 580 किलोमीटर की रेंज देती है।

Hyundai Ioniq 5 में 72.6 kWh बैटरी पैक और एक्सल-माउंटेड सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 214 bhp और 350 Nm का टॉर्क पैदा करती है। हुंडई 350 किलोवाट डीसी चार्जर का उपयोग करके केवल 18 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक प्रभावशाली चार्जिंग समय का दावा करती है।

ड्राइव रेंज और परफॉरमेंस

BYD Seal का प्रीमियम वेरिएंट सिंगल चार्ज पर 650 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। ये केवल 5.9 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। दूसरी ओर, Hyundai Ioniq 5 सिंगल चार्ज पर 630 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज प्रदान करती है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

BYD Seal में थ्री-स्पोक मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ईवी में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और लेवल 2 एडास दिया गया है।

दूसरी ओर, Hyundai की इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर 12.3 इंच के डिजिटल कंसोल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ कनेक्टेड कार तकनीक और बोस साउंड सिस्टम के 60 से अधिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं।

कीमत

BYD Seal की कीमत 41 लाख रुपये से 53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं, Hyundai Ioniq 5 के एकमात्र वेरिएंट की कीमत 46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार्स पर दे रही है 3 लाख से भी ज्यादा का डिस्काउंट, ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ

टाटा डीलर प्री-फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिना बिकी यूनिट्स पर जबरदस्त छूट दे रही है। Nexon EV Prime पर 2.30 लाख रुपये की नकद छूट के साथ 50000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। टियागो ईवी की MY2023 यूनिट को 65 हजार रुपये तक के लाभ के साथ खरीदा जा सकता है जिसमें 50 हजार रुपये का ग्रीन बोनस और 15 हजार रुपये का एक्सचेंज शामिल है।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी पॉपुलर Nexon EV सहित कई इलेक्ट्रिक कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, Punch EV को पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। आइए, उपलब्ध छूट के बारे में जान लेते हैं।

Pre-facelift Tata Nexon EV

टाटा डीलर प्री-फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिना बिकी यूनिट्स पर जबरदस्त छूट दे रही है। Nexon EV Prime पर 2.30 लाख रुपये की नकद छूट के साथ 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। वहीं, Nexon EV Max पर 2.65 लाख रुपये से अधिक नकद छूट और 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। हालांकि, ये छूट स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर है।

Tata Nexon EV

2023 में निर्मित Nexon EV के सभी वेरिएंट पर 50 हजार रुपये का ग्रीन बोनस और 2024 मॉडल पर 20 हजार रुपये का ग्रीन बोनस मिलता है। हालांकि, फेसलिफ्टेड मॉडल पर कोई नकद छूट या एक्सचेंज बोनस नहीं है।

Tata Taigo EV

टियागो ईवी की MY2023 यूनिट को 65 हजार रुपये तक के लाभ के साथ खरीदा जा सकता है, जिसमें 50 हजार रुपये का ग्रीन बोनस और 15 हजार रुपये का एक्सचेंज शामिल है। इस बीच, नए 2024 मॉडल पर 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

Tata Tigor EV

टियागो ईवी कॉम्पैक्ट सेडान पर कुल 1.05 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसमें 75 हजार रुपये की नकद छूट के साथ-साथ सभी वेरिएंट पर 30 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। हालांकि, ये ऑफर केवल 2023 निर्मित मॉडलों पर लागू है।

यामाह ने अचीव किया 300 Blue स्क्वेयर आउटलेटस का माइलस्टोन, कॉल ऑफ दी ब्ल्यू से हुई थी शुरुआत

Yamaha Motor India ने आज यानी 8 मार्च को घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत में 300 Blue Square Outlets खोलने की उपलब्धि हासिल कर ली है। ब्लू स्क्वायर डीलरशिप हाल ही में लॉन्च किए गए R3 और MT-03 बेचते हैं। इसके अलावा ये डीलरशिप Aerox 155 YZF-R15 V4 YZF-R15S V3 MT-15 V2 FZS-Fi Version 4.0 FZS-Fi Version 3.0 FZ-Fi Version 3.0 और FZ-X भी बेचते हैं।

नई दिल्ली। Yamaha Motor India ने आज यानी 8 मार्च को घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत में 300 Blue Square Outlets खोलने की उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दें कि ब्लू स्क्वायर डीलरशिप यामाहा की हाई-लेवल डीलरशिप हैं, जो अपने ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती हैं।

Call of the Blue से हुई शुरुआत

ब्रांड ने 2018 में Call of the Blue ब्रांड अभियान शुरू किया था और ब्लू स्क्वायर शोरूम उस अभियान का हिस्सा थे, जो 2019 में शुरू हुआ था। डीलरशिप में यामाहा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ब्लू थीम है।

Blue Square Outlets पर उपलब्ध प्रोडक्ट

ब्लू स्क्वायर डीलरशिप हाल ही में लॉन्च किए गए R3 और MT-03 बेचते हैं। इसके अलावा, ये डीलरशिप Aerox 155, YZF-R15 V4, YZF-R15S V3, MT-15 V2, FZS-Fi Version 4.0, FZS-Fi Version 3.0 FZ-Fi Version 3.0 और FZ-X भी बेचते हैं।

कहां कितने आउटलेट?

कंपनी के पास Fascino 125 FI Hybrid, Ray ZR 125 FI Hybrid और Ray ZR Street Rally 125 FI Hybrid स्कूटर भी हैं। इसके अतिरिक्त ये आउटलेट यामाहा के अपैरल और एक्सेसरीज की विशेष रेंज भी प्रदर्शित करते हैं। पूरे भारत में संचालित 300 ब्लू स्क्वायर शोरूम में से, यामाहा के दक्षिणी भारत में 129, पूर्वी भाग में 81, पश्चिमी क्षेत्र में 54 और उत्तरी भाग में 37 आउटलेट हैं।

BYD कर रही तीन और इलेक्ट्रिक कारें भारत लाने की तैयारी, जानें क्या है प्लान

चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD भारतीय बाजार में अक्रामक तरीके से अपना विस्तार करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में नई Electric Cars लाने का मन बना रही है। कंपनी की ओर से अगले कुछ सालों को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD के लिए भारत लगातार महत्वपूर्ण बाजार बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की योजना भारत में जल्द ही अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से आने वाले कुछ सालों में कितनी कारों को लाया जा सकता है।

कंपनी कर रही है तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की इलेक्ट्रिक कंपनी बीवाईडी भारत में जल्द ही और नई कारों को ला सकती है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की योजना अगले कुछ समय में तीन नई कारों को भारत में लॉन्च करने की है। इसके साथ ही कंपनी अगले तीन सालों में देश के इलेक्ट्रिक कार बाजार में 85 फीसदी हिस्से को कवर करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी भारत में विस्तार को लेकर भी काम कर रही है। कंपनी का मानना है कि भारत अगले कुछ समय में जापान से भी बड़ा बाजार बनकर उभर सकता है।

सर्टिफिकेशन हासिल करने की तैयारी

जानकारी के मुताबिक बीवाईडी देश में इलेक्ट्रिक एसयूवी Atto 3 के जरिए ARAI से होमोलोगेशन सर्टिफिकेशन हासिल करने पर काम कर रही है। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद 2500 यूनिट की आयात मात्रा पर प्रतिबंध हट जाएगा। होमोलोगेशन देश में बने या आयातित सभी वाहनों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों के तहत सड़क योग्यता के लिए वाहनों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है।

लॉन्च की है नई कार

बीवाईडी की ओर से हाल में ही भारत में नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया गया है। कंपनी ने लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार BYD Seal को फरवरी 2024 में 41 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है।

कैसा है पोर्टफोलियो

बीवाईडी फिलहाल भारत में तीन कारों को ऑफर करती है। इनमें से एक सेडान सील, दूसरी एसयूवी Atto3 और E6 हैं। जबकि आने वाले समय में सी लायन, टैंग और डॉलफिन जैसी कारों को भी भारतीय बाजार में लाया जा सकता है।

शाहजहां मामले में क्या छुपाना चाहती हैं ममता

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

बंगाल में शाहजहां शेख ने उनसे पूछताछ करने के लिए गई ईडी की टीम पर अपने लोगों से हमला करवा दिया था। इसके बाद वह 'सरकारी कागजों' में फरार हो गया था। ईडी ने उसके खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवा दी। ऐसे मामलों में सामान्यतया पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन पुलिस ने ज्यादा रुचि ईडी की टीम के खिलाफ कार्रवाई करने में दिखाई।

तब उन्होंने 'ममता बनर्जी' वाला सूत्र अपनाया। शाहजहां को सीबीआई को नहीं दिया। जो करना हो, कर लो। सारा बंगाल देख रहा है। आखिर ममता बनर्जी शाहजहां को इस सीमा तक जाकर भी क्यों बचाना चाहती हैं? यह प्रश्न शेषनाग की तरह फन तान कर उसके सामने खड़ा है। ममता बनर्जी को किस बात का डर है? दूसरे दिन हाई कोर्ट फिर आदेश देता है। शाहजहां को बंगाल पुलिस की सुरक्षा से निकाल कर सीबीआई को सौंप दिया जाए। लगता है हाईब्रिड तक ममता सरकार के शाहजहां को बचाने के सारे हथियार खत्म हो गए हैं। आखिर शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में पहुंच गया है। सुना है इसको लेकर ममता बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं। पार्टी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि रैली प्रदेश की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में होगी या शाहजहां के पक्ष में'

बंगाल में शाहजहां शेख ने उनसे पूछताछ करने के लिए गई ईडी की टीम पर अपने लोगों से हमला करवा दिया था। इसके बाद वह 'सरकारी कागजों' में फरार हो गया था। ईडी ने उसके खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवा दी। ऐसे मामलों में सामान्यतया पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन पुलिस ने ज्यादा रुचि ईडी की टीम के खिलाफ कार्रवाई करने में दिखाई। पर तब तक इस नए शाहजहां के बारे में यौन शोषण व जमीनें हड़पने के कई मामले सामने आने लगे। लोग, विशेषकर महिलाएं, सडक़ों पर उतरने लगे तो शाहजहां के खिलाफ नए-नए केस दर्ज होने लगे। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अलबत्ता ममता बनर्जी ईडी के खिलाफ जरूर भाषण देती रही। यह भी बताती रही कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। अब बंगाल की पुलिस को इतना तो पता ही था कि यह शाहजहां मुगल वंश का शाहजहां नहीं है, बल्कि तृणमूल वंश का शाहजहां है। इसलिए उसने कूट भाषा को समझ कर शाहजहां को पकडने की बजाय उसे छिपाने में सारी शक्ति खर्च कर दी। लेकिन इसे ममता का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उसके शाहजहां की एक के बाद एक करतूत सामने आती गई।

यहां तक कि उसके आदमी सुंदर लड़कियों को उनके परिजनों के सामने ही उ कर ले जाते थे। उनके अपने घर में या पार्टी कार्यालय में ले जाकर उनसे बलात्कार करते थे। लगता था, उन्होंने अपनी इस गतिविधि को भी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा मान लिया हो। जब बंगाल पुलिस यौन शोषण पीड़ित महिलाओं की पक्षधर होने की बजाय शाहजहां की पक्षधर बन गई तो लोग कोलकाता हाई कोर्ट की शरण में गए। वैसे भी अब तक शाहजहां भी सक्रिय हो गया था और लोगों को अपने गुर्गों को माध्यम से धमकाने लगा था। उच्च न्यायालय ने शाहजहां को गिरफ्तार न करने पर प्रदेश सरकार के रवैए पर हैरानी जाहिर की और प्रशासन को उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन लोग जानते थे कि प्रदेश सरकार की रुचि उसे बचाने में है, न कि गिरफ्तार करने में। प्रदेश में संदेशखाली में शाहजहां के शासन के काले चि_ सामने आ रहे थे। इसलिए हो-हल्ला बढ़ता जा रहा था। मामला यहां तक पहुंच गया था कि प्रदेश सरकार को कोई न कोई सफाई देना जरूरी हो गया था कि वह बताए कि वह तृणमूल नेता शाहजहां को आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? 'वह मिल नहीं रहा', यह बहाना अब काम नहीं आ रहा था। तब ममता बनर्जी के भतीजे मैदान में उतरे। जिस प्रकार ममता बनर्जी कई शाहजहां की सहायता से बंगाल का प्रशासन चला रही हैं, उसी प्रकार उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस का प्रशासन चला रहे हैं। अभिषेक ने बाकायदा एक प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार तो शाहजहां को पकडना चाहती है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई हुई है। वैसे भी शाहजहां को 'भागे हुए' अब पचपन दिन हो ही गए थे। तब हाई कोर्ट ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकार की बहानेबाजी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए ही नहीं कहा, बल्कि यहां तक आदेश दिया कि उसे प्रदेश पुलिस के अलावा ईडी या सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती हैं। जाहिर है हाई कोर्ट के इस आदेश से ममता के साम्राज्य में हलचल मचती।

अब शाहजहां को छिपाना मुश्किल था। खतरा यह हो गया था कि यदि ईडी या सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो कहर टूट पड़ेगा। इसलिए उसे तुरंत बंगाल पुलिस की सुरक्षा में लेना पड़ेगा अन्यथा वह ईडी या सीबीआई की गिरफ्त में आ जाएगा। तब पता नहीं क्या-क्या उगल दे। इसलिए तुरंत बंगाल पुलिस ने 'गिरफ्तारी' की ढाल में उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। लेकिन साथ ही अपनी सफलता का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया कि बंगाल पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है कि शाहजहां उसके शिकंजे से बच नहीं सका। पुलिस को लगता था बंगाल के लोग उसके इस आदेश से धोखे में आ जाएंगे। ममता बनर्जी के लोग अपनी इस सफलता पर बाकायदा नाचने लगे। लेकिन यह शोर शराबा ज्यादा देर नहीं चल सका। ममता और उनका भतीजा अभी यह नकली फुलझडियां चला ही रहे थे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शाहजहां तुरन्त सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। अब मामला टेढ़ा हो गया था। हाई कोर्ट ने कहा था शाम साढ़े चार बजे तक अपराधी को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। आम तौर पर होता यह है कि इस प्रकार के मामलों में अपराधी कोर्ट की तरफ भागते हैं कि मुझे सीबीआई के हवाले न किया जाए। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा वकील। सरकार अपराधियों की इस प्रकार की अपीलों का विरोध करती है। लेकिन शाहजहां के मामले में उलटा हुआ।

बंगाल सरकार रात को ही दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय की ओर भागी। गुजारिश यह थी कि हुजूर किसी तरह हमारे शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में जाने से रोकिए। उधर साढ़े चार बजे का घंटा बज रहा है। सीबीआई के अधिकारी बंगाल पुलिस के दरवाजे पर खड़े हैं, हाईकोर्ट का आदेश लेकर। शाहजहां को हमारे हवाले कीजिए। बंगाल पुलिस का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है शाहजहां को सीबीआई से बचाने के लिए। सीबीआई के अधिकारी पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे वगैरह दिया हो तो दिखा दें। लेकिन कोई स्टे नहीं है। दिल्ली में ममता के वकील गुहार लगा रहे हैं, हुजूर यह मसला बहुत जरूरी है। सब काम छोड़ कर तुरंत सुनवाई करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई जल्दी नहीं देखता। वह तारीख दे देता है। अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब उन्होंने 'ममता बनर्जी' वाला सूत्र अपनाया। शाहजहां को सीबीआई को नहीं दिया। जो करना हो कर लो। सारा बंगाल देख रहा है। आखिर ममता बनर्जी शाहजहां को इस सीमा तक जाकर भी क्यों बचाना चाहती हैं? यह प्रश्न शेषनाग की तरह फन तान कर उसके सामने खड़ा है। ममता बनर्जी को किस बात का डर है? दूसरे दिन हाई कोर्ट फिर आदेश देता है। शाहजहां को बंगाल पुलिस की सुरक्षा से निकाल कर सीबीआई को सौंप दिया जाए। लगता है हाईब्रिड तक ममता सरकार के शाहजहां को बचाने के सारे हथियार खत्म हो गए हैं। आखिर शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में पहुंच गया है। सुना है इसको लेकर ममता बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं। पार्टी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि रैली प्रदेश की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में होगी या शाहजहां के पक्ष में? इस तरह ममता सरकार दोगला रवैया अपना रही है।

संपादक की कलम से

नकली दवाओं का बाजार

भारत में नकली दवाओं के उत्पादन और प्रसार का बाजार करीब 35,000 करोड़ रुपए का है। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने व्यापक स्तर पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और औसत बीमार आदमी को बेची जा रही हैं! कितनी बीमारियां घनीभूत हो रही हैं और कितनों पर मौत का साया मंडरा रहा है? यह बाजार इतना व्यापक कैसे बना, यह हमारी प्रशासनिक और जांच संस्थाओं पर बड़ा सवाल है। ये नकली दवाएं, जिन्हें औषधि कहना ही गलत और पाप है, किसी गांव में या उपेक्षित कस्बे के किसी कोने में चुपचाप नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में धड़ल्ले से बनाई जाती रही हैं। गाजियाबाद में औषधि विभाग, अपराध शाखा और पुलिस के हालिया छापे में 1.10 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। इनके अलावा, कंपनी कितनी दवाइयों का उत्पादन और वितरण कर चुकी होगी, इसका कोई निश्चित आंकड़ा छापा एजेंसियों ने नहीं दिया है। गाजियाबाद से लेकर यह नापाक और जानलेवा धंधा तेलंगाना, महाराष्ट्र तक फैला है। कोई गंभीर सजा नहीं। कोई गंभीर वार नहीं। कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप और खौफ नहीं। आश्चर्य है कि जहां से नकली दवाएं पकड़ी गई हैं, वे मधुमेह, रक्तचाप और गैस सरीखी गंभीर बीमारियों की ब्रांडेड औषधियों की नकली दवाएं थीं। दवा बनाने वाली कंपनी ने ब्रांडेड औषधियों के असली पत्तों, पैकेजिंग और प्रिंटिंग मशीनों का जुगाड़ कहां से किया? अथवा नकली 'बार कोड' कैसे छाप दिए? या फर्जी बैच नंबर कैसे लिख दिए गए? ये बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक सवाल हैं। आश्चर्य तब ज्यादा होता है, जब इन फर्जी कंपनियों के प्रतिनिधि डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन्हें लुभावनी पेशकश के पैकेज दिए जाते हैं, जाहिर है कि ऐसे डॉक्टर भी नकली दवाएं लिखते होंगे! वे भी अपने पेशे, नैतिक संकल्प और मानवीय जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। अमरीका और यूरोपीय देशों ने भी शिकायतें की हैं कि भारत में 20-25 फीसदी दवाएं नकली बेची जाती हैं। बेशक भारत की आबादी 142 करोड़ से अधिक है।

उतने ही अनुपात में लोग बीमार होते हैं, लिहाजा उतनी ही दवाओं की मांग बनी रहती है। चिंतित पहलू यह भी है कि ऐसे नकली बाजदवा कारोबारियों को जो कानूनी सजा मिलती रही है, वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। अधिकतर मामलों में वे जमानत पर छूट जाते हैं या रसूखदारों की सिफारिशों पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। दरअसल यह परोक्ष रूप से हत्या के मामले हैं। चूंकि यह धंधा ही देश के साथ शत्रुता के समान है, लिहाजा यह देशद्रोह भी है। नई 'न्याय संहिता' में इसका दंड तय किया गया होगा, लिहाजा अब उन धाराओं में इन कारोबारियों को दंडित किया जाना चाहिए। हमने तेलंगाना का जिक्र किया था। तेलंगाना सरकार ने 'मेग लाइफ साइंसेज' द्वारा निर्मित 33 लाख रुपए से ज्यादा की तीन दवाओं की जांच की थी। उनमें औषधि का कोई भी तत्त्व नहीं पाया गया। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने खुलासा किया था कि उन नकली दवाओं में केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिलाया गया था। तेलंगाना में पकड़ी गई कंपनी ने कागज पर हिमाचल में मुख्यालय होने का दावा किया था, लेकिन वहां भी ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई। न जाने ऐसी कितनी कंपनियां देश में 'जहर' बेच रही हैं? बीते सप्ताह उत्तराखंड में भी ऐसे ही नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। चूंकि ये सभी दवा निर्माता इनसान की जिंदगी से खेलते रहे हैं, लिहाजा इन्हें भी 'मृत्यु-दंड' दिया जाना चाहिए। हमारा सुझाव अतिशयोक्ति वाला हो सकता है, लेकिन जो लोग मौत के विक्रेता हों, तो उन्हें कैसा दंड दिया जाए और कैसे प्रावधान हैं, चलो, उन्हें अदालत के विशेषाधिकार के अधीन सौंपते हैं। यह हजारों करोड़ का कारोबार देश की प्रख्यात दवा कंपनियों के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि उन्हीं के ब्रांड पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि ये नकली दवाइयां रसूखदार एजेंटों के जरिए सरकारी अस्पतालों में भी सप्लाई की जाती रही हैं। यानी सामूहिक नरसंहार का खेल खेला जा रहा है। क्या सरकार को यह साजिश, कुकर्म और तिजोरियां भरने के लालच का दुष्चक्र नहीं पता? हम यह मानने को तैयार नहीं हैं।

राय

मन, मकसद और मंसूबे

विकास के नए स्रोत पर खड़ी हिमाचल सरकार खुद को चिन्हित करती हुई, नागरिक आशाओं की पैरवी कर रही है। राजनीतिक घटनाक्रम के अतीत से निकल कर सुक्खू सरकार के पैगाम अपनी तीव्रता के केंद्र बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। गारंटियों की इतिला के बाद विकास की गंगा के साथ मुख्यमंत्री के संदेश स्पष्ट हैं और इसी आधार पर कांगड़ा व हमीरपुर के नाम दर्ज 861 करोड़ अपनी कहानी बता रहे हैं। लाभान्वित विधानसभा क्षेत्र मुखातिब हैं, तो सरकार की प्राथमिकताएं भी चमत्कार कर रही हैं। वर्षों से एक नए बस स्टैंड की उम्मीद में हमीरपुर की करवटें बदल रही हैं। करीब 70 करोड़ की लागत से बनने जा रहे बस स्टैंड निर्माण का मुहूर्त आशाजनक है, तो इसी तरह पर्यटन राजधानी के ख्वाब कांगड़ा में मुख्यमंत्री के कदमों की आहट सुन रहे हैं। पहली फेहरिस्त में पर्यटन प्राथमिकताओं का आगाज बनखंडी के चिडियाघर में चहक रहा है, तो नगरोटा बगवां के केंद्र में महक रहा है। छह सौ करोड़ की लागत से चिडियाघर का स्वरूप वाकई पर्यटन के जंगल में मंगल करने का इरादा रखता है, तो नगरोटा में 241 करोड़ की पर्यटन परियोजनाओं का शृंगार आने वाले कल का महत्त्व बता रहा है। हो सकता है राजनीतिक समीकरणों की खिलखिलाहट में विकास के नक्शे भी नए अंदाज में गरज रहे हों, लेकिन उम्मीदों के गुलदस्ते लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब मन, मकसद और मंसूबों की नई हाजिरी लगा रहे हैं।

कांगड़ा का सियासी चित्रण हर सरकार में देखा और समझा जाता है। इस बार भी बेदखल विधायकों के प्रकरण के दो छोर, दो इतिहास और दो नेताओं की युगलबंदी में राजनीतिक खनन कर गया। ऐसे में राज्यसभा चुनाव की गणना में कई भूगोल, तो कई दुर्ग बन गए हैं। सरकार से छह, लेकिन सत्ता से कुल नौ विधायक छिटके हैं, तो अब विकास के मायने भी बदल सकते हैं। इसलिए कांगड़ा की भूमि पर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद नगरोटा बगवां में देखा गया। यहां संसदीय क्षेत्रों की परिपाटी में कांगड़ा का दूसरा भाग अब हमीरपुरी हवाओं का मूल्यांकन है, इसलिए बनखंडी की शोहरत का सदन अलग हो जाता है। इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की देखरेख में, देहरा में गर्दन उठा रही इमारतें बताती है कि इस ताजपोशी का गणित कहां ठीक बैठता है। अब विकास के गलियारे एक तरह से सियासत के भी गलियारे हैं।

अतः विकास की शब्दावली सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, कई बार पथराव भी है। कांगड़ा के एक छोर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पुष्पित हुआ, तो दूसरे छोर में नगरोटा बगवां पल्लवित हुआ। ऐसे में कांगड़ा की पर्यटन राजधानी कहीं आज की राजनीतिक राजधानी ही न हो जाए। यह इसलिए भी कि नगरोटा बगवां के साथ लगती कांगड़ा जिला की राजधानी यानी धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्तावित परिसर गहन उपेक्षा के बादलों से घिरा किससे फरियाद करे। इसी संघर्ष में नागरिक समाज वर्षों से जूझ रहा है और एक विधायक का सियासी सफर रूठ रहा है। कांगड़ा के नाम करोड़ों की राशि, लेकिन सीयू परिसर के ढाई सौ करोड़ बचाने के लिए तीस करोड़ भी उपलब्ध नहीं। प्रश्न अब यह है कि सरकार अगर बागी विधायकों को सबक सिखाते-सिखाते कहीं इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता को भी सबक न सिखा दे। ऐसे में नौ बागी विधायकों के सियासी माजरे में हलकों की जनता को भी उपेक्षित किया जाता है, तो यह अन्याय है। कांगड़ा की पर्यटन राजधानी के होर्डिंग्ज अगर केवल नगरोटा बगवां से रू-ब-रू हैं, तो ऐसा क्यों न माना जाए कि अब इन फिजाओं का घर्षण ही नया सियासी पर्यटन है।

निखिल शर्मा

हर काम में करें महिलाओं का समावेशन

आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा हासिल की गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सफलताओं का जश्न मनाना जरूरी है, ताकि हर महिला में कुछ नया करने की संजीवनी भर जाए, उनमें नए पंख लग जाएं'

'यत्र नार्यस्तु पूजयंते, रमंते तत्र देवताः', जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यहां पर पूजा का अर्थ कोई रोली फूल चढ़ाने से नहीं है, बल्कि महिलाओं को शिक्षा, उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक कार्य में उनका महत्व एवं समावेशन करने से है। इतिहास गवाह है कि जब-जब भी अक्रमण्यता बढ़ी है, तब-तब महिलाओं ने अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया है। भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था, लेकिन इसमें गिरावट मध्ययुगीन काल के दौरान आई जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बन गई। इन परिस्थितियों के बावजूद कुछ महिलाओं ने राजनीति, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में सफलता हासिल की थी। आधुनिक भारत में महिलाएं न केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं, बल्कि गांव में भी आज महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान, मुखिया के पद पर काम कर रही हैं तथा नए युग की पढ़ी-लिखी लड़कियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष आकर समावेशन के साथ आगे बढने की जरूरत है। आज महिलाएं गांव की चौपाल से लेकर वायुयान उड़ान और अंतरिक्ष तक जाने में सफल हो रही हैं।

महिला दिवस का दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, भाषायी और आर्थिक विभाजनों की परवाह किए बिना उनकी असाधारण भूमिकाओं और उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। इस आम दिन को खास बनाने की शुरुआत 1908 में महिला मजदूर आंदोलन के कारणवश महिला जागरूकता दिवस मनाने की परंपरा से शुरू हुई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में 15000 महिलाओं ने नौकरी के घंटे कम करने तथा बेहतर वेतन के साथ अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था और अगले वर्ष 1909 में अमरीका ने इसे पहला महिला दिवस घोषित किया। 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया गया। तब से लेकर धीरे-धीरे यह दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में इस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाने को मान्यता दी और तब से लेकर यह महिला दिवस महिलाओं की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है 'इंस्पायर इंक्लूजन'। महिलाओं को स्वयं शामिल होने के लिए प्रेरित करने, उनमें अपनेपन की भावना, अपनी प्रासंगिकता और सशक्तिकरण का समन्वय हो, महिलाओं के समावेशन के लिए कार्य करने की भी आवश्यकता है। महिलाओं के साथ भेदभाव उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार एवं जहां उनकी उपस्थिति न हो, तो वहां इसके कारण का सवाल उठाने की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत आधार पर भी महिलाओं और लड़कियों को समझना, उनको महत्व देना और उन्हें हर कार्य में शामिल करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होना चाहिए। किसी भी देश के विकास के लिए जितना जरूरी वहां का ढांचागत विकास है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि मानव विकास भी समानांतर रूप से हो। गांव के अंदर महिला मंडल का भवन तो है, लेकिन अगर महिलाएं अपने सशक्तिकरण की बात नहीं करती हैं या फिर मोबाइल फोन हाथ में होने से अगर आप इंटरनेट व कैशलेस लेन-देन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि मानव विकास में कहीं कमी है और मानव विकास में महिलाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। अगर महिला पढ़ी-लिखी है, तो वह सभी आधुनिक मानव विकास के मानकों को जानती है। उसका परिवार प्रगति की राह पर अग्रसर है। न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा पर फोकस करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 यह कहती है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचितों, जैसे महिलाओं और ट्रांसजेंडर की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित करने का प्रावधान भी है ताकि सभी लड़कियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्र की क्षमता का निर्माण किया जा सके।

समग्र शिक्षा में शामिल करते हुए लड़कियों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कई पग उठाने का प्रावधान है, जिनमें बालिकाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए, उनके आवास व गांव के समीप स्कूल खोलने, उनको निशुल्क वर्दी व किताबें प्रदान करना, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों व महिला शिक्षकों के लिए आवास बनाना, सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक स्टाइपेंड देना, लड़कियों के इंक्लूजन के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम चलाना, पाठ्य पुस्तकों से लेकर लर्निंग सामग्री तक लैंगिक संवेदनशीलता रखना तथा छठी से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलना तथा इनका दायरा बढ़ाना शामिल है।

महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए यह नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित हो सकती है, अगर इसका क्रियान्वयन ठीक से हो। शिक्षा के साथ महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर महिला स्वस्थ है तो वह प्रसन्न, सक्रिय, सृजनशील, समझदार व योग्य महसूस करते हुए परिवार, समाज और देश को उन्नत कर सकती है। आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा हासिल की गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सफलताओं का जश्न मनाना जरूरी है, ताकि हर महिला में कुछ नया करने की संजीवनी भर जाए, उनमें नए पंख लग जाएं। विभिन्न महिला संगठनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप व समाज को महिलाओं के पक्ष में काम करना होगा।

हास्य रस

मोहे ब्रज बिसरत नाहीं

मथुरा कन्हैया लाल (श्रीकृष्ण) आ तो गए, लेकिन उनका मन होली के आते ही व्याकुल हो उठा। राधा तथा अन्य गोपियों की याद उन्हें सताने लगी। उद्धव से बोले- 'उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाहीं'। उद्धव बोले- 'भगवन्-आपने ही मथुरा आने की जल्दबाजी की। अभी आप कह रहे हैं कि आप ब्रज को भुला नहीं पा रहे हैं। ब्रज को भुलाना संभव भी नहीं है। आपने वहां वर्षों रास रचाया है। गोपियों की दही-मक्खन की मटकियां फोड़ी हैं और होली पर खूब गुलाल-अबीर उड़ाया है। मैंने तो आपसे कहा भी था कि मथुरा होली के बाद चलेंगे, लेकिन आपने मेरी कहां मानी और मुझे भी ले आए। बोलो अब क्या करें।' कन्हैया लाल बोले- 'करना तो क्या है, जिस तरह मैं आज यहां बेचैन हूं, उसी तरह वहां गोपियां आकुल होंगी। क्या हम रंग वाले दिन वहां जा सकते हैं।' उद्धव ने कहा- 'जा तो क्यों नहीं सकते। होली खेलकर दूसरे दिन अपने 'पुष्पक' से मथुरा लौट आएंगे। बरसाने की होली तो मैं भी कैसे भुला सकता हूं।' 'लेकिन, गोपियों को पुनः अकेला छोड़ूंगा तो उन्हें मेरी याद फिर से तरोताजा नहीं होगी?' 'होगी क्यों नहीं, अभी वे आपको कौनसा भुला पायी हैं। मैं उन्हें समझाने गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था- 'हमारे हरि हारिल की लकरी।' उद्धव ने कहा तो कन्हैया लाल बोले- 'मैं कुछ समझा नहीं ऊधो।' 'महाराज, उनका कहना है कि जैसे हारिल पक्षी अपनी चोंच में हमेशा पतला तिनका दबाए रहता है, वैसे ही हमारी जिह्वा पर तो सदैव श्रीकृष्ण का नाम रहता है।'

उद्धव बोले। कन्हैया लाल बोले- 'फिर तो उद्धव हमारा वहां होली खेलने जाना कम खतरनाक नहीं है। गोपियों की यह दशा तो मुझसे देखी नहीं जाएगी।' 'फिर आप होली किसके साथ खेलेंगे।' उद्धव ने प्रतिप्रश्न किया तो कन्हैया लाल सिंहासन पर बैठ गए, पल भर को निमग्न हो गए। उद्धव ने फिर कहा- 'भगवन्, क्या सोचने लगे। असली होली का आनंद तो गोपियों के साथ ही है। इसलिए मेरी मानो तो गोकुल चलें। हालांकि गोपियों के चेहरों के रंग फीके पड़ गए हैं। उनमें उल्लास और उमंग नहीं बचा है। परंतु हो सकता है आपकी रंग भरी पिचकारियां देखकर उनका मन फिर से प्रफुल्लित हो उठे।' कन्हैया लाल पसोपेश में पड़ गए। हौले से उद्धव से बोले- 'मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा उद्धव। मैं होली खेलना भी चाहता हूं तथा गोपियों को भुला देना भी चाहता हूं। लेकिन दोनों ही बातें असंभव हो गई हैं। मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ। गोकुल जाना ठीक रहेगा?' उद्धव भाव विह्वल हो गए, बोले- 'भगवन्, आप मथुरा में ही बने रहिए। गोकुल जाना ठीक नहीं है। गोपियां आपको मथुरा आने नहीं देंगी। आप कहें तो मैं एक बार पुनः जाकर उनसे होली भी खेल आऊं और उन्हें समझा भी आऊं?' कन्हैया लाल के नेत्र भर आए, बोले- 'हां उद्धव, यही ठीक रहेगा। गोपियों के पास जाना अब ठीक नहीं है। सुनो थोड़ा गुलाल मेरा भी लेते जाना और उनके माथे पर लगा देना। मैं इस बार होली नहीं खेल पाऊंगा?' उद्धव भी उदास हो गए और गुलाल की पोटली लेकर गोकुल के लिए रवाना हो गए। कन्हैया लाल मथुरा में रंज लेकर गुमसुम सोते रहे। गोकुल न जा पाने का दुःख उन्हें कम नहीं था।

पूरन सरमा

इनसाइड

एफटीए पर बात करते समय घरेलू उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हैं: पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में कहा कि मोदी सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करते समय हमेशा घरेलू उद्योगों को उससे होने वाले लाभ को ध्यान में रखती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे दिन गए जब भारत दुनिया की शर्तों को स्वीकार करता था। ईएफटीए के सदस्य आइसलैंड लीशटेंस्टीन नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करते समय हमेशा घरेलू उद्योगों को उससे होने वाले लाभ को ध्यान में रखती है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य पर नजर रखते हैं कि भविष्य में ना केवल इसका (एफटीए) प्रभाव सकारात्मक हो बल्कि वार्ता करते समय हम संतुलित, निष्पक्ष और न्यायसंगत एफटीए पर ध्यान देते हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में इस मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें आने का संकेत दिया। ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ब्लाक ने एफटीए के लिए चल रही बातचीत को खत्म कर लिया है। ईएफटीए के सदस्य आइसलैंड, लीशटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, DA बढ़ने के बाद अब इतनी हो जाएगी सैलरी

गुरुवार को मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दो तोहफा दिया है। बीते दिन कैबिनेट ने डीए और एचआरए में बढ़ोतरी का एलान किया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी कर दिया है। डीए के इजाफा के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा हुआ है। चलिए जानते हैं कि अब कर्मचारी कि सैलरी कितनी हो जाएगी।

नईदिल्ली। गुरुवार को कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का एलान किया। डीए में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होना तय है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। बता दें कि जब भी डीए 50 फीसदी हो जाता है तो यह बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि अब से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी भी बढ़ गई है। डीए के बढ़ोतरी के साथ एचआरए भी बढ़ जाता है। सरकार ने कर्मचारियों को मिल रहा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया है।

फरवरी में म्युचुअल फंड इनफ्लो 23% बढ़ा, 2 साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा इक्विटी म्यूचुअल फंड

माना जाता है कि विषयगत फंडों के लिए बड़े पैमाने पर रुचि और नए फंड ऑफरिंग (एनएफओ) के लॉन्च ने म्यूचुअल फंड के इनफ्लो को प्रभावित किया है।

परिवहन विशेष न्यूज

म्युचुअल फंड इनफ्लो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शन है। कई निवेशक इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। फरवरी में म्यूचुअल फंड इनफ्लो में तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में म्यूचुअल फंड में 26866 करोड़ रुपये का इनफ्लो दर्ज हुआ है। यह जनवरी इनफ्लो से 23 फीसदी ज्यादा है।

नईदिल्ली। म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेश के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शन है। आज फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फरवीर में म्यूचुअल फंड इनफ्लो में पॉजिटिविटी देखने को मिली है।

रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में म्यूचुअल फंड में 26,866 करोड़ रुपये का इनफ्लो देखने को मिला है। यह अभी तक 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। माना जाता है कि विषयगत फंडों के लिए बड़े पैमाने पर रुचि और नए फंड ऑफरिंग (एनएफओ) के लॉन्च ने म्यूचुअल फंड के इनफ्लो को प्रभावित किया है।

जनवरी में म्यूचुअल फंड में 21,780 करोड़ रुपये का प्रवाह रिकॉर्ड किया गया था। जनवरी इनफ्लो से 23 फीसदी ज्यादा इनफ्लो फरवरी में नोटिस किया गया है।

म्यूचुअल फंड के आंकड़ें

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मंथली सिस्टेमैटिक इन्वेस्टनमेंट प्लान (एसआईपी) योगदान जनवरी के 18,838 करोड़ रुपये को पार करते हुए 19,186 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।

एएमएफआई के मुख्य कार्यकारी वेंकट चलसानी ने कहा

जैसा कि हमने फरवरी 2024 के आंकड़ों पर गौर किया, हमने देखा कि एसआईपी अकाउंट में वृद्धि हुई है। इसमें 49.79 लाख नए एसआईपी पंजीकरण के साथ कुल 8.20 करोड़ हो गया है। यह निवेशकों की अनुशासित धन संचय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फरवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये का इनफ्लो देखा गया, जो लगभग पिछले महीने के समान ही था। भारी प्रवाह डेट-ओरियेंटिड स्कीम के 63,809 करोड़ रुपये, इक्विटी योजनाओं के 26,866 करोड़ रुपये और हाइब्रिड योजनाओं के 18,105 करोड़ रुपये के योगदान से प्रेरित था।

मजबूत प्रवाह ने फरवरी के अंत में प्रबंधन के तहत नेट एसेट को पिछले महीने के 52.74 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 54.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के विश्लेषक मेल्विन सैंटारिटा ने कहा

इस साल फरवरी में प्रवाह मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक था, जब इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड में 28,463 करोड़ रुपये का प्रवाह देखा गया था। साथ ही, नवीनतम प्रवाह इक्विटी फंडों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 36वां महीना है। महीने के दौरान इक्विटी सेगमेंट को आठ नए फंड लॉन्च से भी मदद मिली, जिससे कुल मिलाकर 8,692 करोड़ रुपये जुटाए गए।

बता दें कि फोकस्ड फंडों को छोड़कर बाकी कैटेगिरी में 533 करोड़ रुपये का बहिर्वाह देखा गया। लिक्विड फंडों में 83,642 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया और कॉरपोरेट बॉन्ड फंडों में 3,029 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह देखा गया। इसके अलावा, समीक्षाधीन महीने के दौरान गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में शुद्ध प्रवाह की मात्रा जनवरी में 657 करोड़ रुपये से बढ़कर 997 करोड़ रुपये हो गई।

सेक्टोरल में सबसे अधिक 11,263 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया। इसके बाद लार्ज और मिडकैप श्रेणी में 3,157 करोड़ रुपये का इनफ्लो देखा गया है। हालाँकि, पिछले महीने में स्मॉल कैप और मिड-कैप में प्रवाह में क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की गिरावट आई।

दिलचस्प बात यह है कि फरवरी में लार्ज कैप में 20 महीनों में तीसरा सबसे बड़ा प्रवाह 921 करोड़ रुपये रहा।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के वरिष्ठ विश्लेषक, प्रबंधक अनुसंधान, नेहल मेश्राम ने कहा

दिसंबर 2023 में एडवांस टैक्स पेमेंट पूरा करने के बाद, कॉरपोरेट्स ने संभवतः छोटी अवधि के लिए अतिरिक्त निवेश योग्य धन को लिक्विड फंड में निर्देशित किया था, जिससे पिछले दो महीनों में भारी प्रवाह हुआ।

20 मई से शुरू होगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से मांगे आवेदन

दूरसंचार विभाग (Telecom Department) ने आगामी स्पेक्ट्रम (Spectrum Auction) से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की हैं। विभाग ने बताया कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन 20 मई 2024 से शुरू होगा। इसमें सरकार मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए 96317 .65 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड्स का ऑक्शन करेगी। टेलीकॉम कंपनियां ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए 22 अप्रैल तक आवेदन भेज सकती हैं।

नईदिल्ली। दूरसंचार विभाग (Telecom Department) ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि आगामी स्पेक्ट्रम ऑक्शन (Spectrum Auction) 20 मई 2024 से शुरू होगा। सरकार मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए 96,317.65 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड्स का ऑक्शन करेगी।

इसमें उन स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन होगा, जो दिवालिया प्रक्रिया (insolvency processes) से गुजर रही कंपनियों के पास हैं। साथ ही, इस साल एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को भी नीलाम किया जाएगा।

डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) से आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। कंपनियां 20 मई को होने वाले ऑक्शन के लिए 22 अप्रैल तक आवेदन भेज सकती हैं।

इस बार जिन 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी होने वाली है, उनमें 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 MHz and 26 GHz बैंड शामिल हैं। इससे पहले कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम रिफॉर्म की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अगुआई में एक समिति बनाने का फैसला भी लिया था।

नीलामी से 10,000 करोड़ की उम्मीद

टेलीकॉम डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस ऑक्शन से उसे करीब 10 हजार करोड़ रुपये मिल जाएंगे। सुनील मित्तल की भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 1,800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के 4जी बैंड में एक्सपायर होने वाले पुराने लाइसेंस को रिन्यू करेंगे।

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के अनुसार, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्रमशः 4,200 करोड़ और 1,950 करोड़ रुपये के एयरवेव्स रिन्यू कराने होंगे। वहीं, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को इस साल कोई स्पेक्ट्रम रिन्यू नहीं कराना है।

ऑक्शन के ठंडा रहने का अनुमान

इस साल स्पेक्ट्रम ऑक्शन को ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद नहीं है। कुछ वक्त पहले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने कहा था कि इस साल कंपनियां स्पेक्ट्रम पर ज्यादा रकम खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने पिछली नीलामी खुलकर पैसे खर्च किए थे। ऐसे में इस बार उनका फोकस एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम को टॉप-अप करने पर ही रह सकता है।

फरवरी में महंगी हुई वेज थाली,नॉन वेज थाली की कीमत गिरी; जानें क्या है वजह

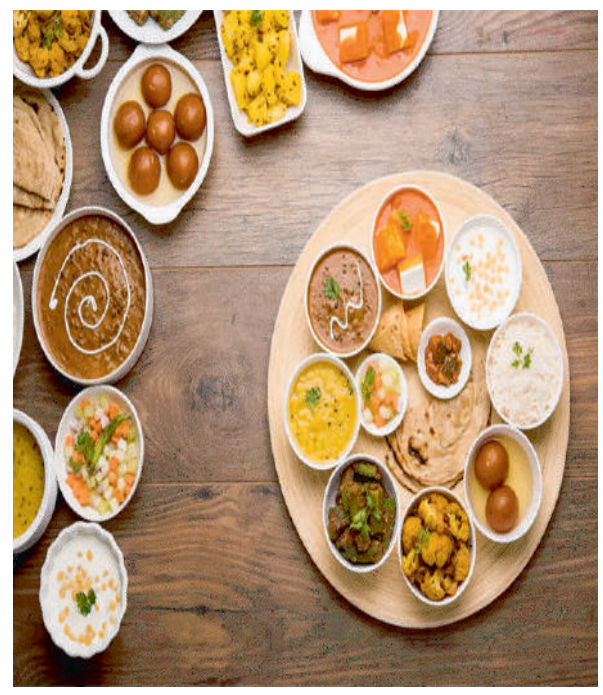

क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फरवरी में वेज थाली की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं मांसाहारी थाली की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल की वजह से वेज थाली की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार चावल और दालें भी महंगी हो गई हैं।

नईदिल्ली। प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल के चलते फरवरी में शाकाहारी थाली की कीमत में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने शुक्रवार को जारी अपनी मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट में कहा कि पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट के चलते मांसाहारी थाली नौ प्रतिशत तक सस्ती हो गई है।

क्यों बढ़ी वेज थाली की कीमत

शाकाहारी थाली, जिसमें रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद शामिल हैं, फरवरी में बढ़कर 27.5 रुपये प्रति प्लेट हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 25.6 रुपये थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, प्याज और टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 29 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि के कारण शाकाहारी थाली की लागत में वृद्धि हुई है।

इसमें कहा गया है कि चावल और दालें भी महंगी हो गई हैं। हालांकि, जनवरी के 28 रुपये की तुलना में यह थाली सस्ती थी। मांसाहारी थाली की बात करें तो उसमें शाकाहारी थाली की तरह सभी समान सामग्री होती हैं, लेकिन दाल की जगह उसमें चिकन होता है।

एक साल पहले की समान अवधि में मांसाहारी थाली की कीमत 59.2 रुपये थी, जो फरवरी में घटकर 54 रुपये हो गई।

हालांकि जनवरी के 52 रुपये की तुलना में यह अधिक है। मांसाहारी थाली की कुल कीमत में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रायलर की होती है। ब्रायलर की कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट के चलते साल-दर-साल आधार पर मांसाहारी थाली कीमत कम रही है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के प्रकोप के चलते रमजान के पवित्र महीने में आपूर्ति और उच्च मांग पर असर पड़ने के चलते जनवरी की तुलना में ब्रायलर की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्मॉल सेविंग स्कीम पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

बिजनेस डेस्क नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी मिल रही है।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी, जो अभी मिल रही है।

वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, 'अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अलग-अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी स्कीमों पर मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अनुसार ही ब्याज मिलेगा।'

अगर बचत योजनाओं की बात करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी। वहीं तीन साल की सावधि जमा पर दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। पीपीएफ और बचत जमा पर भी ब्याज दरें क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई हैं, जिन्हें जनता काफी पसंद करता है।

किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और यह निवेश 115 महीनों में मैच्योर होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 की अवधि के लिए 7.7 प्रतिशत पर रहेगी। मौजूदा तिमाही की तरह मासिक आय योजना के लिए निवेशकों को 7.4 प्रतिशत ब्याज दर देगी। सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को नोटिफाइड करती है। इनमें खासकर वे योजनाएं हैं, जो डाकघर से संचालित होती है। रिजर्व बैंक ने मई 2022 से बेंचमार्क रीपो रेट 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी है। इससे बैंक भी जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। RBI ने हालांकि इस साल फरवरी से लगातार पिछली पांच मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में पॉलिसी रेट पर कोई बदलाव नहीं किया है।

देश में बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च के पहले हफ्ते में 6.55 अरब डॉलर की हुई बढ़त

मार्च के पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 6 .55 अरब डॉलर बढ़कर 625 .63 अरब डॉलर हो गया। एक सप्ताह पहले कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2 .97 अरब डॉलर बढ़कर 619 .07 अरब डॉलर रहा था। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

नईदिल्ली। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक मार्च को समाप्त सप्ताह में 6.55 अरब डॉलर बढ़कर 625.63 अरब डॉलर हो गया। इससे एक सप्ताह पहले कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.97 अरब डॉलर बढ़कर 619.07 अरब डॉलर रहा था।

अक्टूबर 2021 में, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल से वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की गिरावट को रोकने के लिए पूंजी भंडार का उपयोग किया, जिससे मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ।

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, एक मार्च को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 6.04 अरब डॉलर बढ़कर 554.23 अरब डॉलर हो गई।

सोने भंडार में तेजी

डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

इस दौरान जहां स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 56.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 48.42 अरब डॉलर हो गया, वहीं विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 18.18 अरब डॉलर रहा।

आरबीआई के मुताबिक, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की आरक्षित जमा भी 4.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.79 अरब डॉलर रहा।

देवभूमि के स्वरूप को बदलने नही दिया जाएगा:- सीएम धामी

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

काठगोदाम रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य कार्यों के 778.14 करोड़ के शिलान्यास व लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि व महिला दिवस पर प्रदेश वासियों को शुभकामनायें देते हुये कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगडने नही दिया जायेगा।*

उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा घटना को अंजाम देने वाले एक-एक दंगाई को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। जिन लोगों ने कानून के काम को रोकने का कार्य किया है जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जांच होगी। उन्हांने कहा प्रदेश में जिन लोगों ने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाया है वसूली भी उन्ही दंगाईयों से होगा।

उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित यह निर्माण कार्य कई साल पहले तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार द्वारा तमाम ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो पूर्व की सरकारों ने इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं किए। आज यह पुनीत कार्य मां शीतला देवी की कृपा से उनके द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र स्थान पर लंबे समय से सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद का खतरनाक षड़यंत्र रचा जा रहा है। सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से कथित धार्मिक स्थल बनाकर उन्हें कब्जाया जा रहा था। सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर लगभग 3500 एकड अधिक भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अतिक्रमण अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। श्री धामी ने कहा सरकार जनता का दुखदर्द समझती है सरकार द्वारा व्यापारियों हेतु वैडिंग जोन बनाये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लैंड जिहाद पर कार्यवाही, नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानूनों पर कुछ लोगों द्वारा काफी बोला गया लेकिन इनके परिणाम आने के पश्चात लोग कानूनों की सच्चाई से रूबरू होकर आज कहा रहे हैं कि देवभूमि में वर्षो के पश्चात अच्छा हो रहा है।

श्री धामी ने कहा कि सरकार द्वारा केवल फैसले ही नहीं लिये जा रहे है, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है समयावधि के भीतर उन योजनाओं को पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य कार्यों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है मां शीतला देवी के आर्शीवाद से लोकार्पण भी उन्ही के द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास हो और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खडे. व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिनरात प्रयासरत हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए ही सरकार दिन-रात प्रयत्नशील हैं। एक विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम ''स्पष्ट विजन'' को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, इसीलिए आज उत्तराखंड में विकास आधारित राजनीति की एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये विकास यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

श्री धामी ने कहा कि आज प्रदेश में इन्फ्रास्क्टचर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, राज्य में पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं।

श्री धामी ने कहा कि रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग स्कूल का निर्माण होने से जहां रोजगार के

अवसर बढेंगे, वही इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा आम जनता को वाहनों से सम्बन्धित कार्यों के लिए इधर उधर चक्कर काटने से आपको मुक्ति भी मिलेगी। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ''विकल्प रहित संकल्प'' सरकार द्वारा कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहयोग से सभी समस्याओं को पार कर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भटट ने कहा कि आज प्रदेश में विकास की लहर चल रही है और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा हल्द्वानी शहर की फिजा भी परिवर्तित होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए अनेकों कार्यों का जो संकल्प लिया है जल्द ही धरातल पर उतरने वाले है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियो को चैक प्रदान किये गये। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत 10 स्वयं सेवी संस्थाओं को 4 करोड 6 लाख 50 हजार के चैक प्रदान किये गये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद की 40 बालिकाओं 10-10 हजार के चैक दिये गये। समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 दिव्यांगजनों को मोटराईजड ट्रायसाईकिल तथा 10 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर दी गई। कृषि विभाग के 25 कृषको को सम्मानित किया गया। बनभूलपुरा घटना मे पत्रकारों के दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से 10 लाख का चैक प्रदान किया।

इस अवसर पर ईजा बैंणी महोत्सव पर वीडीयो मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा लांच की गई। कार्यक्रम में सुनिधि एवं छोलिया सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कार्यक्रम का संचालन नवीन पांडेय ने किया।

कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह बिष्ट, सरिता आर्या, रामसिंह कैडा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्यमंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, सुरेश भटट, दीपक मेहरा, दिनेश आर्या, मजहर नईम नवाब, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरम्वाल, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, साकेत अग्रवाल, पूर्व मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, मुकेश बोरा, नवीन भटट, रंजन बर्गली, ध्रुव रौतेला, विनीत अग्रवाल, जेड ए वारसी, प्रताप बोरा, प्रकाश हर्बोला के साथ ही सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा, नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई, प्रबंध निदेशक दीपक जैन, एसडीएम हलद्वानी परितोष वर्मा, रामनगर राहुल शाह, तहसीलदार सचिन के साथ ही मातृशक्ति, गणमान्य उपस्थित थे।

पंजाब में 13 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे रोडवेज मुलाजिम, मांगें न मानने के विरोध में लिया गया फैसला

पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से 11 मार्च को सभी बस डिपुओं पर गेट मीटिंग व रैलियां की जाएंगी और 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से बस डिपुओं में बसें रोक दी जाएंगी। 13 मार्च को मुकम्मल हड़ताल करके यूनियन के सदस्य सुबह 10 बजे मोहाली से पंजाब विधानसभा की ओर कूच करेंगे।

चंडीगढ़। मांगों को लेकर संघर्षरत पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन ने अब 13 मार्च को मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। यूनियन इससे पहले 11 मार्च को सभी परिवहन डिपुओं पर गेट मीटिंग व रैलियां करेगी और 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से सभी डिपुओं में बसों को रोक दिया जाएगा।

यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यह फैसला परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी मान ली गई मांगों को भी लागू करने में अड़ंगा लगाए जाने से तंग आकर लिया है। यूनियन के सदस्य 13 मार्च को मोहाली से पंजाब विधानसभा की तरफ मार्च भी निकालेंगे।

लुधियाना में हुई प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल की अध्यक्षता में यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में रेशम सिंह गिल ने कहा कि राज्य सरकार बार-बार बैठकें बुलाकर मान ली गई मांगों को तोड़-मरोड़ कर लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, एमडी के साथ हुई बैठकों में लिए गए फैसलों को परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा लागू करने में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निलंबित कांट्रेक्ट मुलाजिमों को आउटसोर्स के ठेकेदारों के पास भेजा जा रहा है और अब छुट्टी व विश्राम की अनुमति भी ठेकेदार से लेने को कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में यूनियन की सभी मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई गई थी लेकिन जब मांगों को पूरा करने संबंधी पत्र जारी किए गए तो विभाग ने कई मांगों को तोड़-मरोड़ कर लागू किया है, जिसे लेकर मुलाजिमों में भारी रोष है। यूनियन के महासचिव शमशेर सिंह, जगतार सिंह, सीनियर उपाध्यक्ष बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह राठ, गुरप्रीत सिंह पननू, बलजिंदर सिंह ने विभाग की धोखाधड़ी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि विभाग जानबूझकर पंजाब सरकार के खिलाफ मुलाजिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है।

सीएम ने दी 134 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं की सौगात, बनेगा ट्रांसपोर्ट भवन

पंचकूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में पंचकूला को करीब 134 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इस योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पंचकूला के लोगों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलेगी। पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है। आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री ने पंचकूला सहित प्रदेश के सभी जिलों के लिए 4223 करोड़ रुपये की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 42.71 करोड़ रुपये से अधिक राशि की नौ परियोजनाओं का उद्घाटन और 91.10 करोड़ रुपये की राशि की तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सेक्टर-3 में 36.49 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित राज्य सूचना आयोग हरियाणा का भवन, पिंजौर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1.77 करोड़ 63 हजार रुपये की लागत से निर्मित 15 अतिरिक्त क्लास रूम, सात लाख रुपये की लागत से सेक्टर-20 में ब्लॉक पिंजौर में प्ले स्कूल आशियाना, 2.71 करोड़ रुपये की लागत से बरोटीवाला लिंक रोड के सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत ब्लॉक पिंजौर के गांव नानकपुर में 43.92 लाख रुपये, ब्लॉक रायपुररानी के गांव बागवाली में 38.07 लाख रुपये और गांव फिरोजपुर में 18.26 लाख रुपये, ब्लॉक मोरनी के गांव भोज जबयाल में 35.90 लाख रुपये, गांव बरवाला में 30.61 लाख रुपये की लागत से जोहड़ों के सौंदर्यीकरण के कार्यों का उद्घाटन किया।

इन परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

मनोहर लाल ने जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया उसमें बस स्टैंड परिसर सेक्टर-5 पंचकूला में 87.52 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट भवन, पिंजौर ब्लॉक के गांव कर्णपुर में 2.98 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लखी शाह बंजारा कम्यूनिटी सेंटर और सांझी डेयरी योजना के तहत गांव रामपुर तहसील रायपुररानी में पहले फेज में 80 पशुओं के लिए 60 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाले शेड का शिलान्यास शामिल है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, परिवहन एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन, उपायुक्त सुशील सारवान, बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, मीडिया सचिव प्रवीन अत्रेय, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

सुरक्षा बलों ने सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी को बचाया, असामाजिक तत्वों ने कर लिया था अपहरण

परिवहन विशेष न्यूज

मणिपुर के थौबल जिले में असामाजिक तत्वों तत्वों द्वारा अपहृत भारतीय सेना के जेसीओ कोंसम खेड़ा सिंह को सुरक्षा बलों ने बचा लिया है। उनको बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने साझा तलाशी अभियान चलाया।

मणिपुर के थौबल जिले में सुरक्षा बलों ने भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) को बचा लिया है। जेसीओ का कुछ असामाजिक तत्वों ने शुक्रवार की सुबह उनके घर से अहरण कर लिया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

परिजनों को पहले से मिल रही थीं धमकियां

उन्होंने बताया कि जेसीओ की पहचान चरंगपत ममांग लेईकाई निवासी कोंसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। कोंसम खेड़ा सिंह शुक्रवार को छुट्टी पर थे। कुछ लोग सुबह नौ बजे उनके घर में घुस गए और उन्हें एक वाहन में ले गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि अपहरण क्यों किया गया है, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया। लेकिन पहली नजर में यह मामला जबरन वसूली का लग रहा है। सेना के अधिकारी के परिजनों पहले इस तरह की धमकियां मिल चुकीं थीं।

सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया तलाशी अभियान

जेसीओ के अपहरण की सूचना मिलने पर सभी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें बचाने के लिए साझा तलाशी अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग-102 पर चलने वाले सभी वाहनों की जांच की गई। आखिरकार शाम साढ़े छह बजे जेसीओ की रिहाई सुनिश्चित हो पाई। मणिपुर में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह चौथी घटना है, जब छुट्टी या ड्यूटी पर तैनात सैनिकों या उनके रिश्तेदारों को असामाजित तत्वों ने निशाना बनाया।

पिछले साल भी सेना के जवान का हुआ था अपहरण

पिछले साल सितंबर में असम रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक सर्तो थांगथांग कोम का घाटी में एक सशस्त्र समूह ने अपहरण किया था और उनकी हत्या कर दी थी। वह मणिपर के लीमाखोंग में रक्षा सेवा कोर (डीएससी) में तैनात थे। दो महीने बाद एक हथियारबंद समूह ने चार लोगों का उस समय अपहरण कर लिया था, जब वे वाहन से पहाड़ी जिले चुराचांदपुर से लीमाखोंग जा रहे थे। चारों जम्मू-कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के जवान के परिवार के सदस्य थे। पांचवें सदस्य (सैनिक के पिता) घायल हो गए थे और भागने में कामयाब रहे। बाद में सेना इलाज के लिए उन्हें दीमापुर ले गई। बाद में उन्हें असम के गुवाहाटी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एएसपी के घर पर भी हुआ था हमला

इस साल 27 फरवरी को मणिपुर पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पर इंफाल शहर में उनके घर पर हमला किया गया था। इस मामले में हमलावर समूह की पहचान अरमबाई टेंगोल (एटी) के रूप में की गई थी। इस घटना के बाद मणिपुर पुलिस के कमांडो ने इफाल और अन्य इलाकों में हथियार डाल दिए थे।

पहली सूची से कांग्रेस का संदेश, लोकसभा चुनाव लड़ने से दूरी बना रहे इन नेताओं को नहीं मिलेगी राहत

कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का एलान किया है। इसमें 15 उम्मीदवार सामान्य (जनरल कैटेगरी), 24 उम्मीदवार एससी-एसटी,ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का एलान किया है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। वे अभी वहीं से सांसद है। जबकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश भी बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा चुनावी मैदान में उतरेंगे।

कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य (जनरल कैटेगरी), 24 उम्मीदवार एससी-एसटी,ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। पहली लिस्ट के जरिए पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव लड़ने से हिचक रहे वरिष्ठ नेताओं को रियायत देने के मूड में नहीं है। पहली सूची में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर सूबे के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी ने इसका संकेत दे दिया है। केसी वेणुगोपाल अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है।

कांग्रेस सूत्रों का कहना कि, पहली लिस्ट के बाद मध्यप्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव बढेगा। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके गृह जिला जोधपुर से तो पूर्व

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी पर जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी अपनी परंपरागत सीट से लड़ने का विकल्प दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनाव लड़ाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

हरियाणा में भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से लेकर किरण चौधरी के भी चुनाव मैदान में उतरने की संभावनाएं हैं। इसी तरह महाराष्ट्र से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार, वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट, माणिकराव ठाकरे के साथ दिग्गज नेता कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी चुनाव लड़ने का दबाव है। दिल्ली में आप के साथ समझौते से मिली तीन सीटों के लिए जयप्रकाश अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी और अल्का लांबा जैसे सूबे के प्रमुख चेहरों के नाम पर विचार किया जा रहा है।

वायुसेना की 4 इकाइयां प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर्स से सम्मानित, राष्ट्रपति ने महिलाओं के लिए कही यह बात

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार वायुसेना की चार इकाइयों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर्स से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चार भारतीय वायु सेना इकाइयों को मानक और रंग प्रदान किया। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल वी.आर चौधरी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री संसद वीके सिंह, प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुए।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें भारतीय वायुसेना के जाबांजों की बहादुरी पर काफी गर्व है। वायुसेना ने आजादी की लड़ाई से लेकर कई युद्ध में विजय हासिल कर देश का मान बढ़ाया। वायुसेना ने न सिर्फ युद्ध जीतकर अपना सर्वोच्च योगदान दिया बल्कि आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम में टेक्नोलॉजी का बखूबी प्रयोग कर स्पेस प्रोग्राम में भी योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद चलाकर दुश्मन को परास्त किया। उन्होंने महिला दिवस पर भारतीय वायुसेना में महिला वायु योद्धाएं, कार्यक्रम में शामिल महिलाएं और सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाएं वायुसेना में शामिल होकर देश का नाम रोशन कर रही हैं।

45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक और 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। बता दें, राष्ट्रपति मानक और रंग किसी सशस्त्र बल की इकाई के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। बता दें, राष्ट्रपति मानक और रंग किसी सशस्त्र बल की इकाई के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान है।

45 स्क्वाड्रन की यह है खासियत

45 स्क्वाड्रन की स्थापना 1959 में हुई थीं। यह फ्लाइंग डैगर्स के नाम से भी मशहूर है। स्क्वाड्रन ने 1960 में पुर्तगाल शासन के खिलाफ गोवा की मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय में भाग लिया था। इसके अलावा, स्क्वाड्रन ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी अहम भूमिक निभाई थी। स्क्वाड्रन पंजाब और राजस्थान सेक्टरों की वायु रक्षा के लिए जिम्मेदार थी। स्क्वाड्रन ने 258 मिसन उड़ाए थे।

221 स्क्वाड्रन की यह है खासियत

14 फरवरी 1963 को वैम्पायर विमान से सुसज्जित बैरकपुर में 221 स्क्वाड्रन की स्थापना हुई थी, जिसे वैलिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। गठन के करीब दो साल बाद ही स्क्वाड्रन को 1965 के भारत-पाक युद्ध में तैनात किया गया, जहां स्क्वाड्रन ने सराहनीय काम किया। अगस्त 1968 में स्क्वाड्रन Su-7 सुपरसोनिक अटैक फाइटर से पुनः सुसज्जित होने वाले पहले स्क्वाड्रनों में से एक था। 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी पूर्वी थिएटर कमांड के साथ स्क्वाड्रन ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। स्क्वाड्रन ने जवाबी कार्रवाई, हवाई सहायता और टोही मिशनों में शानदार काम किया।

11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट की यह है खासियत

11 बेस रिपेयर डिपो अप्रैल 1974 में अस्तित्व में आया था। स्थापना ओझर, नासिक के रखरखाव कमान के तहत हुई थी। 11 बेस भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख और एकमात्र लड़ाकू विमान बेस रिपेयर डिपो है। डिपो ने सबसे पहले Su-7 विमान की मरम्मत की थी। इसके बाद तो डिपो ने मिग-21, मिग-23 और मिग-29 विमानों के वेरिएंटो सहित तमाम विमानों की मरम्मत की है। 509 सिग्नल यूनिट की स्थापना एक मार्च 1965 में हुई थी। वर्तमान में यह मेघालय में वायु रक्षा दिशा केंद्र के रूप में काम कर रही है। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में यूनिट का योगदान सराहनीय था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023